बयान दें कि इस तरह की बातें क्यों कि जा रही हैं । क्या टेंशन है राजेन्द्र नगर में ? वहां शांति है । कालेज के मामले को लेकर, जो प्योरली ऐडमिनिस्ट्रेशन का मामला है इसको कम्यूनल रंगत दी गई । कम्यूनल रंगत देने के बाद इस प्रकार के हालात पैदा किये जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के तरीके दिल्ली की फिजा को बिगाड़ने के लिये, यहां पर टेंशन पैदा करने के लिये, यहां की हालात को बिगाड़ने के लिये, अख्तयार किये जा रहे हैं ।

इसलिये सरकार इस मामले में बयान दे और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको छोड़े, यह मेरी मांग है ।

**श्री ओम प्रकाश त्यागी** (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, इस टाइम पर दिल्ली की सिचुएशन बड़ी खराब है यह नगर देश की राजधानी है और यहां पर जिस प्रकार का आदर्श हम पेश करेंगे वैसा देश में होगा । यह सौभाग्य है कि यहां पर कोई कम्यूनल या दूसरे प्रकार की भावनायें जाग्रत नहीं हुई हैं । मैं नहीं समझता हूं कि इस फिजा को बिगाड़ने के लिये सरकार क्यों उतावली हो रही है । मैं चाहता हूं कि इसको रोका जाये और गवर्नमेंट को इस पर बयान देना चाहिये ।

MR. CHAIRMAN: You are repeating what Shri Madhok has said. The Minister of Parliamentary Affairs, Shri Raghu Ramaiah, has taken note of the submissions that have been made by the two Members. He will convey it to the Government.... (*Interruption*)

---

**14.08 hrs.**

## MOTION RE: TWELFTH REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES

**श्री मधु लिमये** (मुंगेर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं इस बहस के बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि मेरे दोनों प्रस्ताव पर साथ साथ बहस होगी या पहले प्रस्ताव पर पहले और दूसरे प्रस्ताव पर बाद में होगी ?

**सभापति महोदय** : पहले तो आप कंसिडरेशन के लिए बोलिए ।

**श्री मधु लिमये** : चर्चा तो साथ साथ होगी न ?

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 24 नवम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था विचार करती है ।"

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That this House do consider the Twelfth Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 24th November, 1970."

**श्री मधु लिमये** : इसका जो विषय है यह बहुत पुराना है और 1966 में जब पी० ए० सी० ने अपनी 50वीं रिपोर्ट पालियामेंट के सामने पेश की उसी समय से इस पर किसी न किसी रूप में सदन में विवाद हो रहा है । आपको याद होगा कि जब भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में नये इस्पात कारखाने बनाए जा रहे थे तो उस समय इस्पात की कमी उत्पन्न हुई और सरकार ने फैसला किया था कि विदेशों से इस्पात मंगाया जायगा । उसके लिये लोगों को अनुमति दी गई लेकिन उसकी कई शर्तें थीं । इनमें से एक शर्त यह थी कि जो फर्म या जो कम्पनी बाहर से इस्पात मंगाएगी वह इस बात का आश्वासन देगी कि हिन्दुस्तान में बना हुआ माल, इस्पात का माल वह विदेशों को निर्यात करेगी । साथ साथ इसके बारे में बैंक गांरटी देने के बारे में भी निर्णय हुआ था ।

[श्री मधु लिमये]

जब पी० ए० सी० ने इस मामले की जांच की तो उस समय के इस्पात सचिव श्री एन० एम० वांचू साहब ने समिति को मेरी राय में जानबूझ कर गलत जानकारी दी थी और समिति को गुमराह करने का प्रयास किया था जिसके फलस्वरूप समिति ने आयरन एण्ड स्टील मिनिस्ट्री को तथा सरकार का जो सालिसिटर है, दोनों को दोषी ठहराया। वांचू साहब ने समिति को उस समय यह कहा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जो सूचना दी गई थी कि इन शर्तों को पूरा किया जाए, समिति ने पूछा कि क्या वित्त मंत्रालय की सूचनाओं को आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर को ठीक तरह से समझाया गया था। इस पर वांचू साहब ने कहा कि इसके बारे में सन्देह की गुंजाइश थी। वास्तविकता क्या थी ? वास्तविकता यह थी कि आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर के कार्यालय ने यानी डिप्टी स्टील कन्ट्रोलर मुखर्जी साहब ने स्वयं पत्र द्वारा पूछा था कि इस सूचना का क्या मतलब है और उनको ठीक तरह समझाया गया था कि इसका यह मतलब है कि पहले किसी न किसी विदेशी फर्म के साथ निर्यात के बारे में करार होना चाहिये, बैंक गारंटी वगैरह के बारे में भी। लेकिन वांचू साहब ने यह जानबूझ कर झूठ गवाही पी० ए० सी० के सामने दी। उस समय एस० सी० मुखर्जी साहब मौजूद थे और उनके सामने जब इस तरह की झूठ गवाही दी जा रही थी तो मुखर्जी साहब का फर्ज था कि वह वांचू साहब को टोकते और कहते कि यह बात गलत है और हमको ठीक तरह सूचना दी गई थी, मैंने स्वयं खुलासा पूछा था और खुलासा दिया गया था। लेकिन एस० सी० मुखर्जी साहब जब खामोश रहे तो इसके बाद इस मामले में यहां पर बहस हुई। उसके बाद सरकार कमेटी कायम की गई। सरकार कमेटी के एक सदस्य ने अपना जो असहमति पत्र जोड़ा उस में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वांचू साहब ने गलत जानकारी समिति को दी, एस० सी० मुखर्जी साहब ने मामले को छिपाया और उन्होंने स्वयं भी समिति के सामने झूठ गवाही दी। इसके बारे में मैंने विशेषाधिकार का सवाल उठाया। मामला विशेषाधिकार समिति के सामने गया। अब मेरी शिकायत यह है कि इस मामले की स्वयं जांच करने के बजाय विशेषाधिकार समिति ने पी० ए० सी से पूछा कि आपकी राय क्या है ? उनकी वे राय लेते तो मुझे कोई उसके बारे में एतराज नहीं था। लेकिन जांच करने का काम प्रिवलेज कमेटी को जब सौंप दिया गया था तो उसको स्वयं जांच करनी चाहिये थी। मुखर्जी साहब से, वांचू साहब से और माथुर तथा दूसरे जिन अधिकारियों का मैंने नाम लिया है उनको सवाल पूछने चाहिये थे और स्वयं किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिये था। लेकिन समिति ने क्या किया ? समिति ने चूंकि पी० ए० सी० के सामने झूठ गवाही दी गई थी, इसलिये कहा कि पी० ए० सी० इस मामले को देखें। पी० ए० सी० ने एक उप समिति कायम की और उस समिति की अपनी जो रिपोर्ट है और पी० ए० सी० की रिपोर्ट है, उसके ऊपर विशेषाधिकार समिति ने विचार किया और उसने यह निर्णय किया कि उनके जो निष्कर्ष हैं उनसे हम लोग सहमत हैं। उन निष्कर्षों को हम लोग जरा देख लें।

मैं केवल निष्कर्ष वाला हिस्सा पढ़ता है।

**सभापति महोदय** : मैं आपका ध्यान रूल 315 की तरफ खींचना चाहता हूं। इस विवाद पर कुल समय आधा घंटा होगा।

**श्री मधु लिमये** : सदन मालिक है। सदन अगर आधा घण्टा चाहता है तो आप उसकी राय ले लें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हम लोग लिखकर दे चुके हैं कि हम बोलना चाहते हैं ।

MR. CHAIRMAN : Rule 315 reads thus :

"Before putting the question to the House, the Speaker may permit a debate on the motion, not exceeding half an hour in duration, and such debate shall not refer to the details of the report further than is necessary to make out a case for the consideration of the report by the House."

SHRI NATH PAI (Rajapur) : I move that time allotted for Shri Madhu Limay's motion be extended to 2 hours.

SHRI RANGA (Srikakulam) : What for does he want two hours ?

SHRI NATH PAI : How much time does my hon. friend want ?

SHRI RANGA : The PAC has already gone into this matter.

SHRI NATH PAI : I think leave is granted and the House agrees to my motion, and so, let us continue with the debate.

AN HON. MEMBER : How does he say that the House agrees ?

SHRI NATH PAI : I did not hear any opposition to my motion.

MR. CHAIRMAN : Since we are governed by this rule and there is a specific rule on the subject, unless a motion is moved for the suspension of the rule....

SHRI NATH PAI : So far as debates are concerned, in this case, I do not think that suspension of the rule is required or will be justified. If there is an allotted time, then the House is absolutly within its competence and right to make a motion to extend the time. If Shri Ranga wants less than two hours, we can make adjustments.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : Let us make it one hour.

SHRI DATTATRAYA KUNTE (Kolaba) : I want to bring to your notice one small point....

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : It should not be more than one hour. We agree with the hon. Minister.

SHRI DATTATRARYA KUNTE : As far as rule 315 is concerned, it refers only to the consideration of the report, and, therefore, the House can discuss the motion and dispose of it within half an hour. But there is another motion which has been moved by Shri Madhu Limaye, for which there is no time-limit. You have, in your wisdom, asked us to speak on both the motions at the same time. Had there been only one motion, for the consideration of the report, then we could have finished it within half an hour. But because you have asked the House to discuss the second motion also for which there is no time-limit, as far as I am aware of the rules, therefore, this question of half an hour need not be there at all.

MR. CHAIRMAN : Let it be one hour Government are also agreeable to one hour.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : Shri Nath Pai is under the impression that rule 315 is binding on us, and he has therefore moved for extension of the time. When there is no time-limit, and there is a motion before the House, nobody should really try to fix a time-limit at this stage. Let the debate go on, and at a later stage, the House may decide whether the debate should conclude or not.

SHRI RAGHU RAMAIAH : I think the the general consensus is to have one hour for this debate.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : No. no. There is another motion before the House for which no time has been allotted. So, let the debate go on and then the House can decide. There is no reason for Shri Nath Pai's motion at this stage.

SHRI S. M. BANERJEE : What is your decision ?

MR. CHAIRMAN : We have extended it to one hour.

**श्री मधु लिमये** : सभापति महोदय, तीन आरोपों के बारे में समिति ने यह राय व्यक्त की है कि वांचू साहब की गलती जरूर हुई लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने वह जानबूझ कर की। दूसरे आरोप के बारे में समिति ने कहा है कि आयात के बारे में गलती ध्यान में आने के पश्चात भी श्री एस० सी० मुकर्जी ने सही तथ्य समिति को नहीं दिया। समिति ने कहा है कि यह गलती तो जरूर हुई है, इसमें लाखों रूपये का नुकसान हुआ है, लेकिन समिति बहुत उदार है। समिति कहती है कि गलती तो हुई है, लेकिन

'It did not tantamount to misleading the Committee'.

बहुत उदार है समिति। तीसरे आरोप के बारे में समिति ने श्री एस० सी० मुकर्जी को पूरा दोषी ठहराया है। मैं इस बारे में पृष्ठ 44 पर दिया गया एक ही पैराग्राफ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "The Committee have accordingly reached the conclusion that Shri S. C. Mukherjee did not correctly present the facts to the Public Acconts Committee during the course of his oral evidence on the question of the changes made in the bank guarantee form. The Committee are, therefore, of the opinion that Shri S. C. Mukherjee has committed a breach of privilege and contempt of the House by mis-representing the position in the matter and thereby misleading the Public Accounts Committee. The fact that such a contempt has been committed by a responsible public servant of Shri S. C. Mukherjee's position has increased the gravity of the offence".

इस गलती का तो बहुत साल पहले पता चल गया था, लेकिन सरकार ने इस अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। इतना ही नहीं, उसको बढ़ोतरी-प्रोमोशन-मिली है और मेरे ख्याल में आज वह ज्वायंट प्लांट कमेटी के चेयरमैन हैं। आज हमको कहा जा रहा है कि सरकार के ऊपर यह मामला छोड़ दिया जाये। यह मालला सरकार के ऊपर क्यों छोड़ दिया जाये? दस साल तक जिस सरकार ने इस तरह का गलत काम करने वाले और लाखों रुपयों का नुकसान करने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, जिस सरकार ने उसको प्रोमोशन दिया, उस सरकार के बारे में यहां सुझाव आ रहा है कि उस अफसर को सजा देने का काम उसको सौंप दिया जाये।

श्री मुकर्जी के दो अपराध बिल्कुल अलग हैं। एक अपराध, एक गलत काम, तो उन्होंने स्टील कन्ट्रोलर के नाते किया, जिसमें घूसखोरी का मामला है और सरकार का नुकसान करने का मामला है। इसके बारे में पब्लिक एकाउंटस कमेटी ने कहा है कि सरकार कार्यवाही करे। इस वक्त मैं इस अपराध की चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर उसके बारे में कार्यवाही करने की बात माननीय सदस्य सरकार को सौंप देना चाहते हैं, तो सौंप दें, हालांकि मैं जानता हूं कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है।

लेकिन श्री मुकर्जी का दूसरा अपराध है इस सदन की एक माननीय समिति के सामने झूठी गवाही देना—शपथ, कसम, लेने के बाद झूठा बयान देना, स्वोर्न टेस्टीमनी में गलत-बयानी करना। उसके बारे में उनको दण्डित करने का काम सरकार को क्यों सौंप दिया जाये, यह मेरी समझ में नहीं आता है। अगर यह मामला सरकार को सौंप दिया गया, तो ये लोग अदालत में जाकर—आप जानते हैं कि कानून में छूटने के लिये पचासों तरीके रहते हैं—कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसके बाद श्री मुकर्जी सेवा-निवृत्त हो जाएंगे—वह जल्दी होने वाले हैं—और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। जब मैंने डिफेक्टिव टायर्ज का मामला, सुरक्षा का मामला, यहां पर उठाया था, तो क्या उन अधिकारियों को भी सेवा-निवृत्त होने का मौका नहीं दिया

गया ? इस बारे में पब्लिक एकाउंटस कमेटी की रिपोर्ट है । सरकार ने उसके बारे में क्या किया ? हमारे जवान सीमा पर देश की रक्षा करने के लिये अपना खून बहाते हैं । उनकों रसद और हथियार पहुंचाने के लिये जो ट्रक इस्तेमाल किये जाते हैं, उनके लिये खराब टायर मंगाये जाते हैं । क्या ऐसा खराब काम करने वाले अफसरों को हम सजा नहीं देंगे ? इस तरह तो यह सरकार जवानों को मौत के मुंह में धकेल रही है । चौधरी रणधीर सिंह के इलाके से काफी जवान आते हैं और ये पाजी और बदमाश लोग इस तरह का काम करते हैं । उनको क्या सजा दी गई ?

सवाल यह है कि वांचू साहब को क्यों बरी किया गया । मैं अपने नोटिस में से एक उद्धरण सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो माननीय सदस्यों में नहीं बांटा गया है, जिसको लाइबरेरी में रखा गया है :

> "Now, my contention is that the whole story woven by Mr. Wancchoo about ambiguity, about two possible interpretations, as also about not translating and conveying properly the Finance Ministry's instructions to the Steel Controller is a concoction pure and simple. There was absolutely no basis for this statement. What is more important is that Mr. Wanchoo knew that there was no basis for making this observation."

फाइल में वह पत्र-व्यवहार पड़ा हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि मुकर्जी साहब ने खुद मिनिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा था और वह उनको दिया गया था । उसके बाद श्री वांचू कमेटी के सामने कहते हैं कि संदिग्धता, एम्बिग्विटी, थी । इसमें एम्बिग्विटी क्या थी ? फिर भी समिति ने उदार होकर उनको बरी कर दिया । क्या हमारे ऊपर यह प्रभाव नहीं पड़ा है कि चूंकि श्री वांचू आई० सी० एस० हैं, इस लिये समिति उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती ? उसका कारण मेरी समझ में नहीं आता है । श्री वांचू को समिति ने बुलाया तक नहीं, उनको छेड़ा तक नहीं । उनसे यह भी नहीं पूछा गया कि जब आप समिति के सामने गवाही देना चाहते हैं, तो क्या आप फाइल्स और पत्र-व्यवहार को पढ़ते हैं या नहीं । फाइल में लिखा हुआ है कि उनको खुलासा मिला है; स्पष्टीकरण का जवाब मिला है । फिर भी समिति श्री वांचू को बरी करती है । वह उन्हें बरी कर दे । वह आई० सी० एस० हैं और—मैं कहना नहीं चाहता—काश्मीरी हैं । आज के राज में उनको कौन पकड़ सकता है ? लेकिन जिस श्री मुकर्जी को समिति ने पकड़ा है, उनके खिलाफ भी वह सख्त कार्यवाही करने से हिचक रही है ।

सबसे पहले मैं इस सदन के अधिकारों की चर्चा करना चाहता हूं । इस केस में किन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या सजा देनी चाहिये, इसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं । इंडियन पीनल कोड की धारा 191 में फाल्स एविडेंस के बारे में कहा गया है :

> "Whoever being legally bound by oath or by an express provision of law to state the truth, or being bound by law to make a declaration on any subject, makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is said to give false evidence."

धारा 193 में सात साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है ।

जैसे क्लाइव या वारेन हेस्टिंग्ज ने कहा था—श्री नाथ पाई बता सकते हैं कि किसने कहा था–कि "आई एम एस्टानिश्ड एट माई माडरेशन", उसी तरह अपने प्रस्ताव को देख कर मुझे कहना पड़ता है कि "आई एम एस्टानिश्ड एट माई माडरेशन ।" जहां सात साल की सजा होनी चाहिए, वहां मैं सात दिनों

[श्री मधु लिमये]

की चर्चा कर रहा हूं। लेकिन फिर भी कुछ माननीय सदस्यों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इस तकलीफ का कारण क्या है? क्या सदन को इस तरह का अधिकार नहीं है?

मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ 90 पर से केवल एक ही वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

> "The power of commitment is truly decscribed as the key stone of parliamentary privilege."

इसको की-स्टोन कहा गया है।

**श्री रणधीर सिंह** : कितनी देर तक।

**श्री मधु लिमये** : मैं उस पर अभी आता हूं:

> "In modern times the indispensability of the power of commitment of anybody responsible to public opinion, whether these functions are legislative or judicial, has been amply demonstrated by experience."

इसमें कहा गया है कि आस्ट्रेलिया और अमरीका में जो हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव हैं, उनको यह अधिकार है और वे उन अधिकारों का इस्तेमाल भी करते हैं।

श्री शकधर ने भी अपनी किताब में इस की चर्चा की है और कहा है कि भारत में भी विधान मण्डलों ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है। यह पुरानी किताब है। उन्होंने पृष्ठ 192 पर दो उदाहरण दिये हैं:

> "In one case in 1956 the Rajasthan Vidhan Sabha committed eight persons to jail to serve a sentence of fifteen days imprisonment for contempt of the Honse. In the other case, in 1960, the Madhya Pradesh Vidhan Sabha committed four persons to prison for contempt till further orders of the House."

इंगलैंड में यह कहा गया है कि किसी भी सत्र की जो मियाद होगी उस सत्र के अन्त तक हाउस आफ कामंस को जेल देने का अधिकार है। लेकिन वहां का सत्र और हमारे सत्र में फर्क है। उनका एक साल का सत्र होता है और उसके बाद प्रोरोग होता है। बीच में जब वह उठते हैं तो स्थगन या एडजर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन हमारे यहां की एक परिभाषा आप ले लीजिये। अगर मान लीजिये कि सदन प्रोरोग होने तक आप जेल दे सकते हैं तो अगर यह 20 तारीख तक सदन चला तो 20 तारीख तक या 22 तारीख तक और उसके बाद जब तक राष्ट्रपति आह्वान नहीं करते हैं तब तक आप लोग जेल दे सकते हैं। लेकिन मैंने 20 दिन, 25 दिन या सात साल की चर्चा नहीं की है मैंने सिर्फ मांग की है कि सात दिन की इनको जेल दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, क्या इसके पहले इस सदन ने कभी जेल नहीं दिया? मेरे सामने यह उदाहरण है और आपकी खिदमत में मैं यह पेश करना चाहता हूं। यह 15 नवम्बर 1968 को हुआ। हमारे माननीय मित्र विरोध दल के नेता उस समय संसद कार्य मंत्री थे। डा० राम सुभग सिंह की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के और सरकार के वह प्रतीक थे। आज उनका नाम काट दीजिये। और राम सुभग सिंह की जगह रघुरमैया साहब का नाम जोड़ दीजिए। इनका प्रस्ताव यह है:

> "This House resolves that the person calling himself Shri Gopal Tripathi who threw some papers from the visitors' gallery on the floor of the House at 3 p. m. today and whom the watch and ward officer took into custody immediately has committed a grave offence and is guilty of contempt of this House. This House further resolves that he be sentenced to simple imprisonment till 6 p. m. on 18th November, 1968."

तीन दिन की जेल आपने दी है। काहे के

लिये आपने दी है ? किसी ने विरोध नहीं किया । मैं यहां नहीं था, बाद में मुझे पता चला । लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया । एक युवक अपने असन्तोष को व्यक्त करने के लिये महात्मा गांधी के इस देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है । बाद में कच्छ के मामले में कुछ लड़कियों ने भी आकर प्रदर्शन किया आप उसको तीन दिन की जेल देते हैं । शांति-पूर्ण प्रदर्शन करने के लिये तीन दिन की जेल और जो जानबूझ कर झूठ गवाही देते हैं जिसके लिये इंडियन पीनल कोड में सात साल की सजा है उसको जब मैं सात दिन जेल देने की बात करता हूं तो बड़ी परेशानी कोमल हृदय जिनके हैं उनको हो रही है । मेरे लिये यह कसौटी का सवाल है । यह टेस्ट केस है और आज मैं सब लोगों की सद्-असद् विवेक बुद्धि को आह्वान करना चाहता हूं, आप के ऊपर मैं यह बोझ डाल रहा हूं किआप यह सोचें कि जो सदन तीन दिन की सजा एक युवक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिये दे चुका है क्या इस सदन में इस तरह की दलीलें आ सकती हैं कि जो झूठी गवाही देता हो, आपकी एक समिति को गुमराह करने की कोशिश करे उसको आप सात दिन की सजा देने में घबरा रहे हैं ··· (**व्यवधान**) ···मैंने तो सात दिन का प्रस्ताव किया है, आप अगर ज्यादा चाहते हैं तो उसके लिये प्रस्ताव कर सकते हैं ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : लेकिन यह झूठ शांतिपूर्ण बोले हैं ।

**श्री मधु लिमये** : यह जो बनर्जी साहब हैं, मेरी प्रार्थना है कि आज शैतान की वकालत करने का काम वह न करें । अगर उनको समर्थन नहीं करना है तो चुप भी साध कर बैठ सकते हैं । और अगर उनको बोलना है तो वांचू साहब को सजा देने के लिये बोलें । मुकर्जी के बारे में बनर्जी को नहीं बोलना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : पत्रकार लोग किसी का भाषण ठीक नहीं छापते हैं या सम्पादक कोई आलोचना करते हैं तो हम लोग चेतावनी देते हैं । उनका मामला तुरंत उठाते हैं । लेकिन यह इतना गंभीर मामला है, आज आचार्य कृपालानी जी को मैं नहीं देख रहा हूं । बराबर कहते हैं कि किसी न्यूनतम कार्यक्रम की जरूरत नहीं है । स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन, काफी है । तो यह स्वच्छ प्रशासन से सम्बन्धित नहीं है ?

**एक माननीय सदस्य** : बिलकुल अस्वच्छ है ।

**श्री मधु लिमये** : बिलकुल अस्वच्छ है । दस साल का मामला आपके सामने आ रहा है । अगर इस मोके को आप छोड़ देंगे तो मैं कहना चाहता हूं और मैं अटल जी से कहता हूं कि आप बहुत ज्यादा इतने जिम्मेदार न बनिये, जल्दी केन्द्र की सरकार आपके हाथ में नहीं आ रही है, इतनी जिम्मेदारी के बोझ से आप अपने को मत दबाइये । आप तो नौजवान हैं, आपको कोई जल्दी की जरूरत नहीं है । हम लोगों को कोई जल्दी की जरूरत नहीं है । जो बुड्ढे लोग हैं वह जल्दबाजी जरूर कर सकते हैं जिस तरह से कि मुल्क का बटवारा किया उसी तरह इसके लिये भी वह जल्दी में हो सकते हैं । लेकिन आप और हम लोग जो हैं उनको कोई जल्दी नहीं । इसलिये दो दो कमेटियों ने इनको दोषी ठहराया है तो इस मौके का फायदा उठाइए और अपनी सदसद-विवेक-बुद्धि तथा अपनी आत्मा की आवाज सुन कर मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन कीजिये ।

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar): I move my amendment.

MR. CHAIRMAN: Not now.

**डा० राम सुभग सिंह** : श्रीमन्, मैं श्री मधु लिमये जी का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव के कुछ अंशों से सहमत नहीं लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उनकी मुख्य-मुख्य बातों का समर्थन

[डा० राम सुभग सिंह]

करता हूं। जो हमारा संशोधन होगा उतना उनसे मुझे मतभेद है। क्योंकि इस सदन को यह अधिकार है कि अगर कोई भी शख्स गलती करे तो उसको सजा देने का फैसला यह सदन कर सकता है और इसी दृष्टि से उस वक्त भी सदन ने वह फैसला किया था और आज जो इस्पात के मंत्रालय में हुआ और जिस बात के दोषी जो आफिसर साबित किये गये, उनके खिलाफ कार्यवाही सदन करे, इस बात को मैं मानता हूं और कठोर कार्यवाही होनी चाहिये जिससे किसी को भी बाद में ऐसी हिम्मत न न पड़े कि बाद में वह इस तरह की गलती करे। लेकिन यहां पर सरकार का भी सवाल आता है। पिछले दस सालों से जो गलतियां उस मंत्रालय में होती रही है उसमें मैं विस्तृत रूप से जाना नहीं चाहता मगर यह गलतियां साबित हो चुकी हैं क्योंकि बगैर निर्यात किये आयात किया गया और करोड़ों का घाटा देश को हुआ और जो कुछ गलत कार्यवाहियां इस मंत्रालय में हुईं उन सारी बातों के चलते देश को महान् कष्ट भुगतना पड़ा। आज भी इस सरकार की गलतियों के चलते सारे लोहे के कारखाने करीब-करीब क्षतिग्रस्त हैं, उत्पादन करीब-करीब ठप पड़ा हुआ है और इस्पात की कीमत जहां 500 प्रति क्विटल कम होनी चाहिये वहां 1800 प्रति क्विटल है। तो अगर सदन को कठोर कार्यवाही करनी है तो इस सरकार पर करनी चाहिये क्योंकि जो भी जनता के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं क्योंकि एस० सी० मुकर्जी से भी बड़ी गललियां करने वाली यह सरकार है और ऐसे लोग इस सरकार में हैं। एस० सी० मुकर्जी और वांचू से भी बड़ी गलतियां करने वाली यह सरकार है। तो मैं यह कहूंगा कि हाउस इस बात को विस्तारपूर्वक देखे किसी दूसरे मोशन के द्वारा लेकिन यहां पर जो सवाल है कि इनको सात दिन की सजा दी जाय इससे भी मैं बहुत हद् तक सहमत हूं लेकिन अगर इतना ही कहा जाये, मैं पढ़ता नहीं हूं अपने अमेंडमेंट को...

**श्री एस० एम० जोशी** : अगर यह सरकार इतनी खराब है तो इसके सुपुर्द क्यों करते हैं, यह सरकार नहीं करेगी।

**डा० राम सुभग सिंह** : अगर श्री जोशी जी इसी तरह समर्थन सरकार का करते रहेंगे तो सरकार कभी नहीं करेगी। अब तक जोशी जी करते रहे...

**श्री एस० एम० जोशी** (पूना) : मैंने सरकार का समर्थन कभी नहीं किया लेकिन आप तो उस सरकार के अंग रहे हैं।

**डा० राम सुभग सिंह** : आप बुजुर्ग हैं, इसलिये मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्षमा चाहता हूं। तो सदन के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए मेरा यह निवेदन है कि सदन उक्त आफिसर को बुलावे, यहां उसको रेप्रिमांड करे और सरकार को आदेश दें, सरकार से अपेक्षा नहीं करे, उम्मीद नहीं करे, सरकार को स्पष्ट आदेश दे कि संविधान की धाराओं के मुताबिक जो अधिकतम सजा हो सके वह उन्हें दे। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि संविधान का उलंघन सरकार करे। उनके जो अधिकार हैं, वह उनको दे, लेकिन अधिकतम सजा उनको दे ताकि सरकार की गल्तियों के चलते आम जनता मारी न जाय, क्योंकि इस्पात मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय रहा है, शुरू से अब तक जिसके चलते जनता काल के गाल में गई है और आज भी जा रही है।

SHRI RANGA (Srikakulam): Mr. Chairman, Sir, I wish to express our sense of gratitude to the Public Accounts Committee and the other Members of the House who have rendered signal service in laying their finger on this particular officer and finding him guilty. It is not always so easy to catch hold of people like this. They are very highly placed, as Mr.

Madhu Limaye said, and are highly connected and then highly involved in ministerial politics. My hon. friend had stated that this has been going on for the past 10 years. I say this has been going on for the last 24 to 25 years ever since the Swaraj Government has come.

The persons holding the Ministry and the various other Ministries might have been different but the party that has held office has been the same. Only a part of it has come over to our side now. But otherwise, the guilty political force was the same. The Public Accounts Committee, from time to time, has been warning the Government to take necessary action against such officers who have been responsible for more heinous crimes and at whose doors more directly the guilt was traced. And yet, it was always possible for the Government to come and say later on that the concerned officer had retired, or had gone out of service, for some reason or other or had died and therefore he could not be punished.

We have heard so many scandals attached to quite a number of industrial houses and one of them was condemned by this Iron and steel Ministry itself and other Ministries too and their name was placed in the blacklist; that was Aminchand Pyarelal. There were several others also who had committed similar crimes against our society. They could not be brought to book; they could not be named; they could not be condemned by the Government themselves.

Who is this Government? These Ministers. These Ministers do not sign on any paper; they do not make themselves responsible for anything; they generally go scot-free. But they give instructions to those officers either wrongly or consciously or unconsciously, and sometimes in collusion with those officers, and those officers have got to put their signatures because they are not afraid of Parliament; they are not afraid of the public; they are protected by their covenants of service; also they are protected by the political authority of these ministers, and therefore they go scot-free. The Ministers escape; and in the end the public interest is being victimised. Long last here was one officer who was fortunate or unfortunate enough to get himself caught by the public Accounts Committee and some MPs.

It is very rare. It has not happened before that any such highly placed officer could come to be directly involved in such a discovery. This gentleman has come to be discovered in this manner.

Who is to be condemned? Is it only this officers? What about the ministers who are behind over a period of years? These ministers, of course, cannot be caught hold of and condemned. Even if one can place his finger on a particular minister—A, B or C—we know what has happened in regard to the then years of forgetfulness in this House. Therefore, this House has been extremely indulgent, most unfortunately for the country and for the House itself, indulgent not because the opposition has been sleepy but because the great majority that takes decisions over such matters prefers to sleep and help the House to sleep. That is how they have been escaping. Why do we find the necessity of taking this action at all? It is to warn not only this officer but the whole gamut of officers who are helping the ministers in executing many of their decisions, recommendations and wishes, which are whispered behind the ministerial doors. It is to warn these officers not to continue the present practice of their doing the dirty work on behalf of many of these ministerial politicians and others who have made politics a kind of practice like lawyers and doctors. Lawyers and doctors have every legitimate right to carry on their practice. But these politicians have not got that legitimate right to carry on this practice, but this practice has been going on through controls, licences and permits, ever since we achieved freedom. It was there during the British days. Then our leaders said, they would like to hang them by the lamp-post. But the moment they came into power, what happened? The man who made himself responsible for that expression is gone to make his peace with God, if he believed in God. But so many of us who believed that he was going to implement it are here on that side as well as this side to pay the penalty of our apology to the country for our failure. So many of us have been complaining about this regime of controls. You may give it any name you like, socialism etc., but controls have come to be a social crime in our country. They have come to be an umbrella under which all kinds of social ills could grow and all

[Shri Ranga]

sorts of criminals could prosper. They prosper under the protection of not only controls but fathers of those controls, namely, ministers, over decades.

The ministers could not use all these powers directly themselves because, thank God, thanks to this democracy, they are not entitled to pass any orders themselves and put their own signatures to those orders. But unfortunately for this democracy also, it gives them the privilege of not affixing their signatures and still getting dirty things done through the signatures of these eminent officers.

There was a time in England when officers used to refuse to put their signatures unless they were completely satisfied about the *bona fides* of the action that they had to take. But that time was gone even in England during wartime. We never had such a regime after we achieved our swaraj.

That is how earlier there was a scandal over the Mundhras. Now, we have got all these scandals—one, two, three, how many ?—from the jeep scandal right down to this, and all these politicians, ministers and other people, have escaped. This gentleman has at long last come before us. Now, what shall we do with him ?

We want to punish him, admonish him and castigate him before the whole country. That itself is big enough punishment. On top of it, we want this Government, led and formed by these ministers, to humble themselves for once before this House and accept the decision of this House that they should punish this man and make a report to this House ; otherwise, they would escape again saying, "We have taken suitable action against this officer", as they have been escaping by giving such excuses. Let them make a report to us. Then we shall see whether they have given appropriate punishment to this man or not, whether they have behaved well or not or whether somehow or other they have whitewashed the whole thing because they would be white-washing their own faces.

This is the punishment that we are suggesting. My hon. friend, Shri Madhu Limaye, would not be satisfied with this much punishment. He would like him to be sent to jail. That is the only bone of contention. Whether he should be sent to jail or not, is a question on which I am not quite clear.

SHRI SURENDRA NATH DWIVEDY (Kendrapara) : Having had previous jail experience.

SHRI RANGA : If it is only possible to send the ministers to jail, I would say, "Yes", but most unfortunately the concerned ministers have not been found guilty in such a direct manner and only this poor fellow could be got hold of. He is only their tool. He is only one among many such officers who have done their dirty work. Therefore I would like to be a little merciful to him.

SHRI RAGHU RAMAIAH : Not to us ?

SHRI RANGA : Not to the ministers ; only to this officer who has done their bad work and has been their victim and their tool.

Therefore, through this arrangement, I would like this House to give a warning to all the officers that whatever may be the protest that they would be getting from these ministers, it would never be possible for them all to escape from punishment at the bar of public opinion of this country and at the bar of this House ; and, also, that it would not be possible for them to get umbrage all the time from these ministers, that a day would come, when, as is the case with this officer, they would be punished not only by this House but also by the very same masters who are responsible for their wrong acts for which this officer is being punished today.

MR. CHAIRMAN : Shri Vajpayee.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : On a point of order. Has the amendment been moved ?

MR. CHAIRMAN : No.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : When will it be moved ? The speeches are all on the amendment.

MR. CHAIRMAN : I know.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : Then I will mention my point of order.

SHRI NATH PAI : Either the amendment is moved or it is not moved.

MR. CHAIRMAN : It is not moved because the amendments are to item 9.

SHRI NATH PAI : A point of order cannot be raised on a matter which is not before the House. If I heard Shri Kunte rightly, he suggested that in case the amendment has been moved, he would like to raise a point of order. Then you replied that there was no amendment before the House. If there was no amendment, a point of order could not be raised in a vacuum or on a non-existent item.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : That is all right. The speeches are being made as if the amendment was before the House.

MR. CHAIRMAN : That is because I permitted discussion of both items 8 and 9 simultaneously. In order to avoid a second speech by them, they are making their point of view clear at this stage.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : Taking as if the amendment is before the House, a point of order can be raised.

MR. CHAIRMAN : When item 8 is adopted, item 9 will come up.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : The difficulty is this. Speeches are being made as if the amendments are before the House. So, I must make my point at the earliest opportunity.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : We fail to understand this. If the amendment has not been moved, how can both the motions be before the House ?

MR. CHAIRMAN : I permitted a simultaneous discussion of both items 8 and 9. Whatever the amendmects to item No. 9 may be, they can be taken up only after item No. 8 has been adopted.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : Since you have allowed discussion on item No. 9 also, along with item No. 8, amendments to item No. 9 also come in. The amendment given notice of by five hon. Members reads :

"That in the motion,—

*for* "committed to jail custody for a week"

*Substitute—*

"summoned before the bar of the House and be reprimanded and the House do further recommend that the Government, in the light of gravity of the offence, administer to Shri S. C. Mukhurjee maximum punishment under the law and report the same to this House."

So far as it says "summoned before the bar of the House and be reprimanded", it is proper. Whether it is sufficient in the circumstances of the case or not, I am not discussing at this stage. But the other part of the amendment, recommending to the Government to punish the officer creates a difficulty. Could a judge ask someone else to pass a sentence ? The judge can pass a sentence. If it is hanging, the executioner will hang him. If it is confinement to jail the jailor will confine him to jail. May I point out to those five hon. Members who have given notice of this amendment....

SHRI RANDHIR SINGH: Six members. I am also there.

SHRI DATTATRAYA KUNTE : I am concerned with the names given here. Anyhow, the more the merrier. He should also enjoy the joke. It may will happen that a lawyer like me, on behalf of Shri S. C. Mukherjee, may take up the stand that the Government could not punish him as an agent of Parliament and whatever punishment they want to inflict he will go scotfree, because this punishment is only for giving false evidence before a Committee of Parliament. So, I want to point out to those hon. Members that even if this amendment is a adopted Government will not be able to punish him. So, I am raising it.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Shri Kunte has raised a point of order which

[Shri Surendranath Dwivedy]

goes into the merits of the amendment. My difficulty is this. Though you have stated that both the motions are before the House for discussion, unless the first motion is adopted no amendments can be moved to the second motion. In order to avoid this difficulty I would suggest that since there is unanimity in this House about the first motion that the report may be discussed, let the first motion be put to the House and adopted. Then amendments can be moved to the second motion and discussion can follow. Members are concentrating their attention on the amendments. Nobody is making a point that the report should be discussed or not ; nobody is disputing that. In order to regularise it, let us proceed in that manner.

MR. CHAIRMAN : Agreeing to the suggestion made by Shri Surendranath Dwivedy, I am putting Motion at Sl. No. 8 to the vote of the House. After it is adopted, I will take up Motion at Sl. No. 9 and the amendments moved to that.

The question is :

"That this House do consider the Twelfth Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 24th November, 1970."

*The motion was adopted*

MR. CHAIRMAN : Now, we take up Motion at Sl. No. 9. Shri Madhu Limaye.

**श्री मधु लिमये** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 24 नवम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था और जिसमें भूतपूर्व लोह तथा इस्पात उपनियन्त्रक श्री एस० सी० मुकर्जी को जान-बूझकर गलत रूप में तथ्य प्रस्तुत करने और लोक लेखा समिति के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने और इस सभा का अवमान करने का दोषी ठहराया गया है, विचार करने के बाद संकल्प करती है कि उन्हें एक सप्ताह के कारावास के लिये भेज दिया जाये।"

MR. CHAIRMAN : Now, there are some amendments to it. There is Amendment No. 1 in the name of Shri R. D. Bhandare. Is he moving the amendment ?

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Sir, I do not want to move the amendment. But I would like to speak later on.

MR. CHAIRMAN : That is a different thing. You are not moving the amendment.

Then, there is Amendment No. 2 in the name of Shri Kanwar Lal Gupta. He is not here ; that is not moved.

Now, Amendment No. 3 is in the name of Dr. Ram Subhag Singh, Shri N. G. Ranga, Shri Nath Pai, Shri Atal Behari Vajpayee, Shri Prakash Vir Shastri and Shri Randhir Singh.

DR. RAM SUBHAG SINGH : I beg to move :

'That in the motion,—

*for* "committed to jail custody for a week"

*Substitute* "summoned before the bar of the House and be reprimanded and the House do further recommend that the Government in the light of gravity of the offence administer to Shri S. C. Mukherjee maximum punishment under the law and report the same to this House."'(3)

MR. CHAIRMAN : There are two more amendments. But since they have come after the required time......

SHRI SHIV CHANDRA JHA : Kindly allow me to move my amendment.

MR. CHAIRMAN: Firstly, Shri Shiv Chandra Jha's amendment came after the required time and, secondly, he has suggested that the House should fine Rs. 5000. The House only imposes punishment. The House does not fine. Then, another amendment is in the name of Shri Dhireshwar Kalita.

SHRI DHIRESHWAR KALITA (Gauhati): Kindly allow me to move my amendment also.

SHRI SHIV CHANDRA JHA (Madhubani): I want to move my amendment.

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRI SHIV CHANDRA JHA; I beg to move:

> That at the end, *after* "week"
>
> *insert*—"and be fined Rs. 5000."

SHRI DHIRESWAR KALITA: I beg to move:

> That in the motion—
>
> *for* "committed to jail custody for a week"
>
> *Substitute* "summoned before the bar of the House and be reprimanded and the House do further recommend that the Government in the light of gravity of the offence administer to Shri S. C. Mukherjee maximum punishment under the law and report the same to this House within seven days."

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : सभापति महोदय, जो मामला सदन के सामने विचाराधीन है उस पर मैं कुछ कहूं इससे पहले मैं मित्रवर श्री मधु लिमये को बधाई देना चाहता हूं। उनकी तत्परता के लिये, उनकी जागरूकता के लिये और उनकी कर्तव्य-परायणता के लिये। दस वर्ष से पहले उठाये गये मामले को उन्होंने छोड़ा नहीं। मामले तो बहुत से सदस्य उठाते हैं, लेकिन उन्हें एक तर्क सिद्ध परिणति तक पहुंचाना, नौकरशाही पर एक कड़ी नजर रखना, संसद को उसके एक अंकुश के रूप में प्रभावी बनाना, यह ऐसे गुण हैं जिन पर मुझे ईर्षा होती है। यह बात अलग है कि मैं 100 फीसदी उनसे सहमत नहीं हो पाता, लेकिन इसके अर्थ यह नहीं हैं कि जिस तरह से वह मामले उठाते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं और अपराधियों को कटघरे में खड़ा करते हैं, उसकी हम सराहना न करें। उनका प्रयत्न अभिनन्दनीय है और इस अर्थ में वह अपने नेता डा० लोहिया की बताई हुई पगडंडी पर चल रहे हैं यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है।

अब मैं इस मामले पर आना चाहता हूं। इस मामले से मेरा गहरा सम्बन्ध रहा है। पब्लिक अकाउन्टस कमेटी ने 1960 में इस स्टील के घोटाले की जांच के लिये जो उप-समिति बनाई थी, दुर्भाग्य से कहिये या सौभाग्य से, मैं भी उसका एक सदस्य था। उसके बाद मामला सरकार कमेटी को सौंपा गया। सरकार कमेटी की रिपोर्ट में एक विमति टिप्पणी है जिसको श्री मधु लिमये ने पकड़ लिया, और उस जानकारी के आधार पर श्री मधु लिमये ने फिर इस मामले को उठाया।

पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सदन की कमेटी है, बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है। उसके सामने अफसर बुलाये जाते हैं। उनसे आशा की जाती है कि वह सही जानकारी देंगे। न वे तथ्यों को छिपायेंगे और न समिति को गुमराह करेंगे। अगर संसदीय समितियों को अफसरों के द्वारा गुमराह किया जायेगा या उससे तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया जायेगा तो यह संसदीय समितियां अपनी सार्थकता खो देंगी। सदन फिर उनके द्वारा प्रभावशाली रूप से कार्य नहीं कर सकता। इसलिये अगर कोई ऐसा मामला प्रकाश में आता है जिससे यह सिद्ध हो सके कि किसी अफसर ने जान बूझ कर किसी संसदीय समिति को गुमराह किया है तो यह बड़ा गम्भीर मामला है।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

श्री मधु लिमये ने इस मामले पर नजर रक्खीं। यह मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गया। अगर प्रिविलेज कमेटी चाहती तो दोनों अफसरों को बुला कर उनसे जिरह कर सकती थी तथा स्वतन्त्र निर्णय कर सकती थी। उस परिस्थिति में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दुबारा तस्वीर में आने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन शायद प्रिविलेज कमेटी ने ठीक ही समझा कि जिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मामला शुरू हुआ उनकी भी राय ले ली जाये। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, जिसका अध्यक्ष आज कल मैं होता हूं, सारे मामले की जांच के लिये एक उप समिति बनाई। प्रो० हीरेन मुकर्जी, श्री कौशिक, श्री सोनवाने और श्रीमती सुशीला रोहतगी जैसे सदस्यों को लेकर एक उप समिति गठित की गई। उस उप-समिति ने श्री वांचू को भी बुलाया और श्री मुकर्जी से भी जिरह की। उस उप-समिति का जो भी निर्णय हुआ उसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने स्वीकार कर लिया और हमने वह निर्णय विशेषाधिकार समिति के विचार के लिए भेज दिया। वह अगर हमारे निर्णय से संतुष्ट न होती तो स्वतन्त्र जांच कर सकती थी और इन अफसरों को फिर से बुला सकती थी। बुलाती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि फिर हमारे मित्र श्री मधु लिमये को यह कहने का मौका न मिलता कि मेरा दिल बड़ा नरम हो गया है।

**एक माननीय सदस्य** : कोमल है।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : कोमल और नर्म में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा निवेदन है कि मेरा हृदय न तो कोमल है और न कठोर है।

**एक माननीय सदस्य** : अटल है।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : अटल के साथ बिहारी भी लगा हुआ है।

लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि श्री वांचू को इसलिये छोड़ दिया गया कि वह आई० सी० एस० हैं। अगर श्री लिमये विश्वास करें तो मुझे उनके मुंह से पता लगा है कि वह काश्मीरी हैं। जब हमने विचार किया श्री वांचू के आचरण पर तो वे आई० सी० एस० हैं या काश्मीरी हैं, यह पहलू हमारे सामने नहीं था, उनके प्रकाश में हमने कोई निर्णय नहीं किया। जो तथ्य सामने थे, उनके उनके प्रकाश में हमने फैसला किया। उससे प्रामाणिक मतभेद रखने का सबको अधिकार है, लेकिन हमने जो निर्णय किये उसके कारण भी पी० ए० सी० ने अपनी रिपोर्ट में दिये हैं।

उदाहरण के लिये एक कारण यह है कि जब यह मामला हुआ उस समय श्री वांचू स्टील मिनिस्ट्री के सचिव नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जो सूचनायें जारी की गई, इंस्ट्रकशंज जारी किये गये उनके बारे में भी श्री वांचू से जो बहस हुई थी वह छः साल बाद हुई। हो सकता है कुछ तथ्य तब तक उनके ध्यान में से निकल गए हों। इसलिये समिति इस परिणाम पर पहुंची कि उन्होंने जान बूझ कर समिति को गुमराह नहीं किया। लेकिन समिति ने इस बात पर टिप्पणी की है कि श्री वांचू पूरी फाइलें पढ़ कर नहीं आये। यह साधारण बात नहीं है, एक बड़ी गम्भीर बात है। भले ही यह मामला विशेषाधिकार उल्लंघन का न हो लेकिन हमारे वरिष्ठ अफसर अगर संसदीय समितियों के सामने पूरी जानकारी प्राप्त किये बिना जायेंगे, गवाहियां देंगे, पूरी फाइलें नहीं पढ़ेंगे तो वे अपने कर्त्तव्यों के साथ न्याय करते और इतनी मात्रा में श्री वांचू दोषी हैं, अपने कर्त्तव्य का ठीक तरह से पालन न करने के।

जैसे श्री मधु लिमये ने कहा है यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और यह स्टील का घोटाला पिछले दस साल से चल रहा है। सरकार कमेटी की रिपोर्ट आ गई। पी० ए० सी० ने भी 1960 में इस पर टिप्पणी की थी कि इस

क्षति के लिये, इस गोलमाल के लिये कौन उत्तरदायी है। सरकार ने अभी तक दोषी अफसरों के खिलाफ कोई कारंवाई नहीं की। यह सरकार की विफलता है जिसके लिये सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।

जहां तक श्री मुखर्जी का सवाल है, समिति गहराई से इस मामले में गई। कहीं हमने उन्हें सन्देह का लाभ दे दिया, कहीं हम इस परिणाम पर पहुंचे कि उन्होंने जानबूझ कर तथ्यों को दबाया, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक बैंक गारन्टी का सवाल है हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने समिति को गुमराह किया।

संसदीय समिति को गुमराह करने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी में रखने लायक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पदच्युत किया जाना चाहिये। अगर हमारे अधिकार में होता और अगर संवैधानिक कठिनाइयां मार्ग में न होतीं तो हम यह सिफारिश जरूर करते कि श्री मुखर्जी को तुरन्त नौकरी से हटा दिया जाये, ऐसा व्यक्ति सेवा में रह नहीं सकता। वह केवल संसदीय समिति को अपमानित करने का दोषी नहीं है, वह सारी लोकतंत्रीय प्रक्रिया के प्रति अपनी अवज्ञा दिखाने का अपराधी है। गवाही देने के लिये जब वह आता है तो सत्य कहूंगा इस आश्वासन के साथ आता है लेकिन असत्य सम्भाषण करता है। उसे क्षमा नहीं किया जा. सकता है। लेकिन सभापति जी, आप संविधान के पण्डित हैं। आप जानते हैं किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को नौकरी से निकालने से पहले कई प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। उसे अपराध की सूची दी जाती है···

**श्री स० मो० बनर्जी :** हमें निकाला गया बिना कोई सूची दिये हुए।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** शायद आप इसी लायक थे। सभापति महोदय, यह मैंने मजाक में कहा है। मैं जानता हूं कि इनको जो निकाला गया, वह भी गलत था।

सभापति महोदय, संविधान हमारे मार्ग में आता है। एक प्रक्रिया है जिसमें से होकर जाना पड़ेगा। उसके लिये हमने रास्ता निकालने की कोशिश की है। सदन के सामने श्री लिमये जी का प्रस्ताव है कि श्री मुकर्जी को सात दिन की सजा दी जाये। अगर सजा ही देनी है तो सात दिन की ही क्यों दी जाय? ऐसा लगता है कि श्री लिमये जी का हृदय भी कोमल है। इसका मतलब हुआ कि कोमलता में केवल डिग्री का सवाल हुआ। सात दिन के बजाय पंद्रह दिन की भी दी जा सकती थी। लेकिन पंद्रह दिन की सजा देने की बात आपने नहीं कही है। कारण यह प्रतीत होता है कि आप भी सोचते हैं कि सात दिन से अधिक ठीक नहीं। अब हम सोचते हैं कि सात दिन देना भी ठीक नहीं है। इस तरह से कोई मौलिक अन्तर नहीं है। मैं उनके गुस्से को समझ सकता हूं। वह शायद ऐसी सजा देना चाहते हैं जो अन्य अधिकारियों के लिये एक उदाहरण बन जाये। लेकिन सजा देने के लिये उन्होंने जो सात दिन की सजा की बात कही है उससे मैं सहमत नहीं। सदन ने कभी कुछ दर्शक दीर्घाओं में प्रदर्शन करने वालों को सजा दी है इसलिये इस मामले में भी सजा दी जाये, क्या यह तर्कसंगत है?

**श्री मधु लिमये :** गम्भीर मामला है।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :** मैं यह मानता हूं कि श्री लिमये जिनको सजा दी गई, उनको सजा देने के पक्ष में नहीं थे। अगर वह उनको सजा देने के पक्ष में नहीं तो किसी और को सजा देने की बात वह कैसे कहते हैं। मैं मानता हूं कि यह गम्भीर मामला है और इसलिये इसमें हमें गम्भीर सजा देनी चाहिए। लेकिन किसी के लिए कोड़ा मारना भी सजा नहीं है और किसी के लिये दो अपमान के शब्द कह देना भी बड़ी सजा है। हमें दंड में एक

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

रेखा खींचनी पड़ेगी। किसी सरकारी अफसर को सदन सामने बुला कर उसकी भर्त्सना करना और फिर सरकार को यह निदेश देना कि इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करो, यह जब हम अपने संशोधन के द्वारा सरकार से कहते हैं जिस संशोधन को डा० राम सुभग सिंह ने पेश किया है और जिसे हमारे लायक मित्र श्री नाथ पाई ने तैयार किया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सदन अपनी किसी जिम्मेदारी का परित्याग करता है। हम सरकार से कह रहे हैं कि संविधान को ध्यान में रख कर, कानून की रोशनी में जिन प्रक्रियाओं में से जाना आवश्यक है, उनमें से जाते हुए अधिक तक सजा दो। हमने यह भी कहा है कि फिर इस सदन के सामने आओ और बताओ कि क्या सजा दी है। सदन यह निर्णय करने के लिये दरवाजा खुला रखना चाहता है कि सजा पर्याप्त है या नहीं है।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर सजा पर्याप्त नहीं होगी तो यह मामला फिर खुलेगा, सदन इस पर फिर विचार करेगा। सरकार हमारे एजेंट के रूप में काम कर रही है। हम किसी जिम्मेदारी का परित्याग नहीं कर रहे हैं।

श्री लिमये के प्रस्ताव पर श्री भंडारे ने एक संशोधन दिया है। मैं उस संशोधन के औचित्य को भी समझता हूं। प्रिवलेज कमेटी में सभी दल हैं। संसद् की वह समिति है। उसने...

**श्री रा० धों० भंडारे** (बम्बई—मध्य) : मैं समझाऊंगा।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : उससे पहले मैं समझा दूं। उस दिन हमारे मित्र श्री लिमये कह रहे थे कि रूल्ज कमेटी की बात माननी चाहिए? तो क्या प्रिवलेज कमेटी की बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन इस मामले में हमें लगता है कि प्रिवलेज कमेटी को जितना जाना चाहिये था वह नहीं गई। इस वास्ते श्री भंडारे के संशोधन और श्री लिमये के प्रस्ताव के बीच में से हमने एक रास्ता निकाला है, हमने एक स्वर्ण मध्य खोजा है और वह स्वर्ण मध्य यह है कि श्री मुखर्जी को सदन के सामने बुलाया जाये, उनकी भर्त्सना की जाये और सरकार को निर्देश दिया जाय कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दो और फिर सदन को उसकी रिपोर्ट दो और बताओ कि जो सजा दी है वह क्या है और फिर सदन फैसला करेगा कि सजा पर्याप्त है या नहीं है संशोधन के प्रकाश में जो संयुक्त है, मैं अपने मित्र से, श्री लिमये से कहूंगा कि अगर वह अपने प्रस्ताव पर बल न दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं सदन से भी कहूंगा कि जो संयुक्त प्रस्ताव है, जिसमें सत्ताधारी दल भी शामिल हो गया है, देर आयद दुरुस्त आयद, उसको स्वीकार किया जाये।

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Like previous speakers, I congratulate Shri Madhu Limaye on the effort he has taken as a result of which this matter has come to this stage in our deliberations. Now we are discussing action against the concerned official for misrepresenting facts and misleading one of our parliamentary Committees. The misdeeds are still there which have to be taken note of, a proper inquiry held and punishment meted out. Whatever misdeeds had happened had gone under the carpet upto now. Now action is sought only on the count of misrepresentation which is serious enough and has to be taken note of. Other things are yet to be done.

Also this should be a grave warning in future to Government and government officials against misrepresenting facts and misleading a parliamentary committee. Parliamentary Committees do not have all the facts before them; only when they suspect there is something wrong somewhere, do they go

into the matter. Unless we get all the material facts and information concerning that matter intact, it will be useless for any parliamentary committee to function in that respect.

These things have gone too far. When the Leader of the Opposition, Dr. Ram Subhag Singh, was speaking, he said this had been going on for the past ten years. It was then amended by Prof. Ranga who said that this had been going on for the past 23 or 24 years. Probably Dr. Ram Subhag Singh gave the figure of 10 years because he joined Government in 1962.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He is always very unkind.

SHRI SEZHIYAN: Because he was there he could see things at close quarters which he could not previously do.

DR. RAM SUBHAG SINGH: I am watching the DMK Government also.

Some admissions had been made on the floor of the House this morning.

SHRI SEZHIYAN: He is welcome to take the job of policemanship over the Tamil Nadu Government, for which we are very thankful to him.

There can be no two opinions that this is a very grave mistake and the concerned officer has committed a breach of privilege and contempt of the House by misrepresenting the position and misleading the PAC.

Whatever may be the punishment to be meted out to him, I am not going into the detail of it. My point is that the Committee of Privileges has gone into the question in detail. They have had as many as eight sittings, not one or two. We spend only two hours on this here. But in the Committee they went into it in detail, sifted all the evidence and came to a certain conclusion. My suggestion is that whatever the findings of the Committee, we should respect them, as far as possible. Only when there is a verious divergence of opinion should we seek to change it. It should not become a fashion for us here to change whatever the committee, on which is represented all the parties. has recommended. Even in the last meeting at which these conclusions were arrived at, very sernior and respected members of House like Shri Hem Barua, Shri Kalita, Shri P. G. Sen, Shri Y. D. Sharma and others were present. They deliberated over 8 sittings and came to certain conclusions. Not that we cannot override their decision if the situation warrants it, but with all respect, I would say that once a parliamentary committee has gone into a matter and submitted their findings, we in the House should accept and implement it unless our view here is at great variance with the Committee's findings, in which case we can refer the matter back to the Committee for reconsideration. As we all know, the parliamentary committee represents the entire House and we should take cognisance of the fact that the Committee was seized of the matter in all its details and has given its findings. Not that the Committee had not taken a serious view of the matter. They say:

> "The fact that such contempt has been committed by a responsible public servant of Shri S. C. Mukherjee's position has increased the gravity of the offence".

So they were aware of the gravity of the offence. They sat through eight sittings, have sifted all the evidence before them and given their report. They say:

> "The Committee are of the view that Shri S. C. Mukherjee deserves to be censured for the contempt of the House committed by him".

Whether he is called to the bar of the House and censured or consure is expressed to him is the same thing, If the Committee had mentioned seven days imprisonment as Mr. Limaye now suggests, I would have accepted it. Not that I am opposed to the amendment moved by Dr. Ram Subhag Singh or Mr. Limaye. My point is that the Committee has arrived at its findings after due deliberation and we have to respect the recommendations of the Committee. Nor do I want the officer to escape-punishment. Even the Committee itself has said that the Government should give him the maximum punishment.

SHRI SURENDRA NATH DWIVEDY: There is no motion to accept the Committee's recommendation.

SHRI SEZHIAYAN: Otherwise, future committees may not be able to function effectively. They will wonder what the House would say and they will not come to any conclusion, and Parliament itself may have to convert itself into Committee and sift all the evidence. So, it is better that we give due weight to the conclusions arrived by the committee and accept their recommendations.

**श्री स० मो० बनर्जी** : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने मित्र, श्री मधु लिमये, को धन्यवाद देते हुए यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री एस० सी० मुकर्जी के बारे में मैं जो कुछ कहूंगा, वह एस० एम० बनर्जी के रूप में नहीं, बल्कि सत्येन्द्र मोहन बन्धोपाध्याय के रूप में।

रामकिशन कुलवन्तराय की जिस फर्म का इस रिपोर्ट में बार-बार उल्लेख किया गया है, वह अमींचन्द प्यारेलाल की फर्म है। मैं समझता हूं कि अमींचन्द प्यारेलाल के जाल में तकरीबन तमाम लोग, चाहे वे मंत्री हों और चाहे किसी प्रान्तीय सरकार के उप मुख्य मंत्री, फंस चुके हैं। हमें यह देख कर ताज्जुब हुआ कि उस कम्पनी के हाथ कितने ज्यादा बढ़े हुए हैं। श्री एस० सी० मुकर्जी तो एक मामूली व्यक्ति थे और वह उनके इशारे पर चला करते थे। लेकिन जब उनके खिलाफ सवालात श्री मधु लिमये और मैंने यहां उठाये, तो किसी शख्स ने कहा—अक्सर पाल बादर्ज यह कहा करते थे कि आप तो ख्वाह-में-ख्वाह यह सवाल उठा रहे हैं, होगा कुछ नहीं, क्योंकि इस कबीना का शायद ही कोई मंत्री ऐसा बचा होगा, जिसको हमने ओबलाइज न किया हो। लेकिन मुझे खुशी है कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने यह मामला गया और काफी दस्तावेज उसके सामने रखे गये, मैं कह सकता हूं कि उसका 99 प्रतिशत श्रेय श्री मधु लिमये को है—और अब यह साबित हो चुका है कि श्री मुकर्जी ने गलतबयानी की। उन्होंने वह गलतबयानी दानिस्ता की या नादानिस्ता, इस सवाल पर निर्णय किया जाना था। कमेटी ने कुछ बातों पर तो प्रकाश नहीं डाला है या कुछ बातों को छोड़ दिया है या बेनिफिट आफ डाउट दे दिया है, लेकिन कुछ बातों के बारे में उसने कहा कि दानिस्ता ऐसा कहा गया है। कमेटी ने कहा :

> "The Committee, however, feel that the requirements of the case would be fulfiled if the disapproval and displeasure of the House in respect of the contempt of the House committed by S. C. Mukherjee is conveyed to him and also to the Government of India for disciplinary action against him."

मैंने भी सरकारी कर्मचारी की हैसियत से बीस साल बिताये हैं—अपने जीवन का बेहतरीन हिस्सा गंवाया है। और मुझे मालूम है कि सेंशर जब हम कहते हैं तो पार्लियामेंट में तो दूसरी बात होती है, वह बहुत बड़ी बात हो सकती है और जहां तक कि सिविल सर्वेन्ट की बात है वह बहुत बड़ी बात हो सकती है लेकिन साधारण सेंशर का पनिशमेंट जो है वह माइनर पनिशमेंट समझा जाता है। सेंशर को सबसे कम माना जाता है। तो मैं यह समझता हूं कि पार्लियामेंट केवल सेंशर करे इससे कोई नजीर पेश नहीं होगी। कोई नजीर कायम करना चाहते हैं कि जिससे नौकरशाही थोड़ा सा डरे और नौकरशाही को यह ज्ञान हो कि अगर कोई गलतबयानी वह करेंगे जिससे कि पार्लियामेंट या उसकी कोई कमेटी मिसलेड हो तो जो दण्ड दिया जाय उनको वह कम से कम ऐसा होना चाहिए कि दोबारा किसी की जुर्रत न हो कि वह ऐसा करे। मैं यह समझता हूं कि वांचू साहब भी इसके दोषी हैं। अटल बिहारी जी को मैंने सुना और मुझे पूरा विश्वास है एक चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने कोई अपने नरम दिल का इजहार या उसका कोई प्रदर्शन नहीं किया, मुझे विश्वास है और केवल

अटल बिहारी जी ही नहीं, बल्कि जितने भी सदस्य हमारे हैं वह माननीय सदस्य हैं और जिस भी आसन पर वह बैठते हैं तो वह एक जज को तरह से बैठते है, इसलिए मैं यह नहीं मानता कि उन्होंने कोई मर्सी शो की होगी लेकिन मैं यह समझता हूं कि वांचू साहब भी दण्ड देने के काबिल थे, उनको भी दण्डित किया जाना था किन्तु वह किसी तरह से बच गए, इसलिये इस कमेटी को दोबारा उस केश को उठाना चाहिए क्योंकि वांचू साहब आज भी मौजूद हैं । वरना यह मजाल हो नहीं सकती एक डिप्टी कंट्रोलर स्टील की कि वह इस तरह की बयानी करे और एक कमेटी के सामने करे। मैं समझता हूं कि जो गवाही उन्होंने दी है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि आउट आफ इग्नोरेंश यह गवाही दी हो। उनको मालूम था। कुछ चीजों को छिपाने की कोशिश की गई क्योंकि यह पर्टीकुलर फर्म जो अमीचंद प्यारेलाल की है उससे कनेक्टेड है, उससे उसके कनेक्शंस थे। मधु लिमये जी ने कहा है कि मामूली मामूली चीजों को लेकर तीन तीन दिन की सजाएं दी गई। अनएम्प्लायमेंट के खिलाफ किसी ने पर्चा फेंका तो उसको तीन तीन और चार चार दिन की सजा दी गई तो सात दिन की सजा जो उन्होंने रखी वह कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सात दिन की सजा देने के बाद क्या यह उचित सजा हो जायगी ? इसलिये मैं समझता हूं कि जो संशोधन आया है डा० राम सुभग सिंह जी का उसमें सरकार को भी देखना है कि सरकार कहां तक उसको कर सकती है या नहीं कर सकती है, वाकई वह दंडित करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। मान लीजिए कि सरकार दंडित करना चाहती है और उस आफिसर के पास कोई ऐसी चीजें हों कि जिससे यह साबित कर सकता हो कि मंत्री महोदय भी उसमें शामिल थे तो मैं चाहता हूं कि वह सारी चीजें आनी चाहिएं और सरकार इस केस को सी बी आई को रेफर करे क्योंकि यह केवल गलतबयानी का ही केस नहीं है। इसमें करप्शन इन्वाल्व्ड है। यह आस्पेक्ट करप्शन का हम लोगों ने देखा नहीं है या कमेटी ने देखा नहीं है क्योंकि उनके सामने जो मसला था वह सीमित था केवल इतना था कि उसने गलतबयानी की है या मिसलेड किया है या नहीं किया गया है। लेकिन किस लिये यह किया गया, किसलिये छिपाने की कोशिश की गई, कितने आदमी इन्वाल्व्ड थे, क्या मकसद था, क्या उसके पीछे कोई करप्शन था, अमीचन्द प्यारे लाल की कोई साजिश तो नहीं थी, यह तमाम चीजें देखी जानी चाहिए और इसलिये मैं समझता हूं और अपने मित्र मधु लिमये जी से मैं कहूंगा कि एक दफा सरकार के सामने भी जाने दें और फिर उसको सजा दी जाय। सेंशर की पनिशमेंट मैं समझता हूं कि काफी नहीं है। हाउस रेप्रिमांड करे लेकिन सरकार के पास जाय तो उसमें लिखा है प्रस्ताव में कि

> "Maximum punishment under the law and report the same to this House."

तो मैं समझता हूं कि अगर सात दिन के अंदर आए या पन्द्रह दिन के अन्दर आए तो बुरा क्या है ? क्योंकि सरकार तो अपना माइंड मेक अप कर चुकी है इस रिपोर्ट के ऊपर। वह केवल सेंशर न होकर अगर सरकार चाहती है कि दंडित किया जाय उनको तो जो अमेंडमेंट श्री कालिता का है कि सात दिन के अन्दर सरकार को रिपोर्ट करनी चाहिये, उसको 15 दिन भी कर सकते हैं। इसलिये मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं श्री मधु लिमये जी से कि हाउस की कोई यूनानिमिटी है और एक राय से हम लोग कह रहे है तो एक दफा सरकार के ऊपर छोड़कर भी देखें कि वाकई में वह करप्शन के खिलाफ है या नहीं, वाकई में उस अफसर के खिलाफ उसका हाथ उठता है या नहीं और वह रिपोर्ट जब यहां पर आये तो अगर वह उचित कार्यवाही नहीं करती है और वांचू साहब के खिलाफ भी कार्यवाही

[श्री स० मो० बनर्जी]

नहीं करती है तो दोबारा यह सदन कंसिडर करे और उसके बाद सदन सजा दे या न दे यह चीज हम देख सकते हैं ।

**श्री क० ना० तिवारी** (बेतिया) : सभापति महोदय, जो संशोधन डा० राम सुभग सिंह जी लाए हैं मैं उसका समर्थन करता हूं और यह मैं अपील करना चाहता हूं मधु लिमये जी से कि यह पहला वक्त होगा कि इस सदन के द्वारा इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी और वह भी एक मत से वह कार्यवाही होगी । इसलिये इसकी जो खूबसूरती है उसको वह नहीं मिटने देंगे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात बहुत ही गंभीर है कि इतना बड़ा पदाधिकारी किसी वरिष्ठ लोक सभा की समिति के सामने इस तरह की गलतबयानी करे । अटल बिहारी वाजपेई जी ने और दूसरे लोगों ने काफी इसके ऊपर रोशनी डाली है । मैं नहीं समझता कि मैं फिर उन बातों को दोहराऊं । लेकिन जब यह बात संशोधन में कही गई है कि सरकार इसके ऊपर क्या कार्यवाही करती है इसकी भी रिपोर्ट सदन के सामने करे तो एक मौका वह भी होगा आपको देखने के लिये और समझने के लिये कि क्या कार्यवाही सरकार ने की । मेरा ख्याल है कि सरकार भी इतने बड़े एकमत से जो बात पास होगी उसकी अवहेलना नहीं कर सकती है । इसलिये मैं उसका समर्थन करता हूं और अपील करता हूं कि श्री लिमये जी इसके साथ में अपनी सहमति प्रकट करें ।

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : I rise to support the motion move by Shri Madhu Limaye and the propose all made therein, that Mr. S. C. Mukherjee be sentenced by this House for seven days, that is, a week. I say so because on the question of merit itself, you will find that the conduct of Mr. Mukherjee, apart from the deliberateness involved in the thing, as I went through the entire report on this question, shows that there was a suppression of fact and misleading. It was not only from the Public Accounts Committee that he was suppressing the facts or misleading, but he was doing that particular thing in a schematic way, to deliberately do it at various levels. For example, it has been mentioned in this report itself that "particularly as the changed form of the bank guarantee had not been shown to the Ministry at any stage before evidence was given on this point." So, this question of change in form, that particular thing, was suppressed not only from the Public Accounts Committee, the change in form that had been done—but he had not brought it to the notice of the Ministry also. So, suppression takes place there also, and then at the Government—level.

Thirdly, you will find that in the enquiry itself, in the dissenting note, a particular fact is mentioned, that Mr. Mukherjee did not bring this fact to the notice of Mr. Wanchoo as well. So, if you see it, it is not only the deliberateness aspect of it. I do not go into the merits, but I go by the report itself. From the report it is obvious that the particular conduct of Mr. Mukherjee was not a more aspect of deliberateness alone ; it was a schematic aspect also which was involved in it to see that this particular thing is suppressed at the level of Government, suppressed at the level of Mr. Wanchoo and suppressed at the level of the PAC, including Members of Parliament. When such is the gravity of the implication of the whole thing, I do not understand why some of our friends are differing somehow on this question.

Then I come to the other things. On the question of gravity, it was not merely gravity, but let us see his conduct. It is mentioned here in the report that "this was unfortunate as it led the Committee to pass strictures against the Government Solicitor which it would not have done had it been apprised of the correct position." So, his conduct has led to this, and the implication or the result of it also implicated an innocent person. The Soliciter for no fault of his, for no crime of his, had strictures passed on him by the Committee because of the conduct of Mr. Mukherjee. Such

is the gravity of the offence and a harsh punishment is called for.

There are two kinds of action: action by the House for breach of privilege and action outside according to the law. One cannot substitute the other. So far as the amendment is conerned, Dr. Ram Subhag Singh and others have suggested so far as the House is concerned only reprimand, but when it is the question of action under law, they have suggested maximum punishment. Mr. Vajpayee was also very elequent when he was touching this aspect. Once they concede that Mr. Mukherjee's conduct calls for maximum punishment under the law of the country, they should not make a distinction when it comes to punishment by the House and say that the punishment should be a milder one, *i. e.* reprimand. I can understand if Mr. Vajpayee had brought forward some extenuating circumstance which will require this Parliament considering a milder sentence. But he has not mentioned any extenuating circumstance. Then why does he say that so far as punishment by the House under the rules of Parliament is concerned, it should be 'komal'? Therefore, it is a clear case. I appeal to the movers of the amendment to withdraw the amendment, so that as Mr. Tiwary said, we can come to a unanimous decision and the officers will take a lesson from this.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): Sir, the actions of Mr. Mukerjee which are being condemned by this Parliament are various. Some of them relate to the functions of this House and some do not. He has tampered with the bond. That is not within the purview of this House by way of privilege or contempt. Then he gave a wrong date about the knowledge when this matter came to light and he gave wrong figures. We are only concerned in this House with his giving false evidence and misleading the House. We are not concerned with how much Government has lost when we are functioning like a court, though, of course, we are concerned with it as a legislature. The only thing we are concerned with now is whether he committed contempt. It is not a question of privilege but contempt.

We are trying to punish him for contempt. I agree with the sentiments expressed that he is guilty of many offences and deliberately so. He tried to tamper with the agreement. He tried to mislead Mr. Rao of HSL saying, "Don't worry about it. I will see that the export covers this amount." It appears as if Mr. Mukerjee had some understanding with the firm Kulwantrai and that also needs probe. What the Government has done is not known yet, but some secret understanding, which smells of corruption, is there. Then he tried to shift the date of knowledge and gave a wrong figure, which is the worst offence. After the 26th October, he says imports were about Rs. 3.9 lakhs whereas the fact is they were Rs. 26 lakhs and more. So, all those facts are there. I agree that he should be punished and punished to the maximum. The original motion of Shri Madhu Limaya says seven days. Whether it is 7 days or 22 days, I do not think will make much difference. The motion says that he will be summoned to the House and reprimanded; then there is a recommendation to the government that he should be given the maximum punishment under the law. The law will cover both the administrative law and compliance with article 311 and also the criminal law of the land.

Some doubts have been expressed here that once he has been punished by this House, the courts may not punish him for the same offence. Therefore, Shri Kunte feels that the second part of the motion will remain ineffective. Of course, it is true that the Government, which is being directed by this motion, to report to the House remains ineffective, the whole thing will remain ineffective. But if the Government pursue the case under the administrative law, the procedure will take time but action can be taken. Similarly, they can take steps under the criminal law also. Because, there is loss to the Government due to his negligence and tampering with documents without lawful authority. So, if the matter is taken to court he will be punished for seven years. Of course, we cannot give a direction to the court as to what punishment to award. It will depend upon the circumstances of the case. So, if the Government take action both under the administrative and criminal law and make a report to this House, the House will be in a position to judge whether Government acted in consonance with the wishes of this House that he must be given the maximum punishment. Therefore,

[Shri Srinibas Misra]

I support this amendment and I hope Shri Limaye will see reason and not press his motion.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: I have heard all the learned speeches and yet I have not got an answer to the point that I raised.

SHRI R. D. BHANDARE: He has not heard all the speeches yet.

SHRI RANDHIR SINGH: Sir, I have given my name and you have not called me,

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat. It is not a party question. The Minister will speak.

SHRI RANDHIR SINGH: I have given notice of an amendment. You are allowing only Members from that side.

MR. CHAIRMAN: Do not show your anger here. Please resume your seat. It is not a party question.

SHRI RANDHIR SINGH: Members from this side should also be allowed to speak.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, बहस ठीक तरह चले, इसलिये यह जरूरी है कि ये लोग भी कुछ बोलें......

SHRI RANDHIR SINGH: I have given notice of an amendment and I have given my name.

श्री मधु लिमये : सरकारी मंत्री के बाद अटल जी का भाषण होता तो ज्यादा मजा आता।

MR. CHAIRMAN: From one hour we have extended the time to two hours. Now it is going even beyond that.

SHRI RANDHIR SINGH: The Minister may Speak in his own vein. We do not mind that. But we should be heard.

श्री शिव चन्द्र झा : संशोधन वालों को भी मौका दें, ऐसा न हो कि केवल इन लोगों को ही मौका दें।

MR. CHAIRMAN: Kindly listen to me. At 4.15 p.m. we have to take up another unfinished debate. Therefore, we must conclude by that time.

SHRI RANDHIR SINGH: I regret very much that people only from that side have been given opportunity. It is very unfair.

श्री नरेन्द्र कुमार शाल्वे (बेतूल) : इसके बारे में आप ने क्या निर्णय किया, क्या बोलने का मौका मिलेगा ?

सभापति महोदय : बोलने का मौका मिलेगा।

श्री रणधीर सिंह : आपने कहा था कि मिनिस्टर बोलेगें, हम क्या यहां भेड़-बकरियां हैं। कमाल कर दिया है, हरियाणा के चेयरमैन हैं, ऐसी बात कहते हैं।

MR. CHAIRMAN: I would again request him to resume his seat.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: When I said I have heard learned speeches, I did not forget that some more learned speeches are yet to come. But I could not anticipate those speeches and so I did not say anything about them.

The motion before the House is a very limited one. It is as regards contempt committed by Shri S. C. Mukherjee of this House. The other aspect of his conduct in the Iron and Steel Ministry or in the office of the Iron and Steel Controller is not directly before the House at this stage. We are considering whether on the evidence that has come and what the Privileges Committee has reported that Shri S. C. Mukherjee has committed contempt of this House by giving false evidence before a committee of this House, what punishment should be meted out to him.

The Privileges Committee had made a certain recommendation. The very fact that the motion of Shri Madhu Limaye is suggesting something different, means that we disagree from the Privileges Committee as regards their

recommendation as to what should be the punishment. Shri Madhu Limaye says that he should be sentenced for seven days and while being critical of that Shri Atal Bihari Vajpayee said that he had been *komal* enough; why not sentence him to sven years and fine also.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I did not say that.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: I do not know whether this House could do it though in the early stages of the British Parliament it did happen.

The point that I want to raise is that the six Movers of this amendment had at the back of their mind the other conduct of Shri Mukherjee in the Ministry itself, but while moving this amendment they have unfortunately not amended the motion of Shri Madhu Limaye accordingly. The motion of Shri Madhu Limaye only refers to the contempt of this House. Therefore what has been at the back of their mind while drafting that amendment does not unfortunately either reflect in the amendment or in the motion moved by Shri Madhu Limaye.

Their amendment says:—

"recommended to Government the maximum punishment under law".

What is the law? It will have to be the law of contempt because he is to be given the maximum punishment for contempt of this House. The Chairman of the Public Accounts Committee is nodding his head.

SHRI NATH PAI: Not nodding, shaking.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: He is nodding it in disapproval. But I am afraid he will have to look into the law and then he will have to come to my point of view. I am prepared to bear with him; I am not in such a hurry. That is why I raised the point of order at an early stage before the amendment was actually moved.

Let them indicate what would be the maximum punishment under the law and for what offence. The offence has been clearly laid down in the motion of Shri Madhu Limaye, that, is, that he has committed contempt of this House. Having committed contempt of this House by giving false evidence he is to be punished for that offence. They are not satisfied with the reprimand. They want to give the maximum punishment. What would be the maximum punishment under the law for contempt?

My hon. friend, Shri Srinibas Misra, wanted to say that the doubt which I have raised would not exist because he also is thinking that by asking the Government Shri S. C. Mukherjee will be punished for the other offence also. Let us not mix the two issues. The Government had been called upon as early as 1966 in the Fiftieth Report of the Public Accounts Committee to take suitable action. If this Government has slept for the last four years, let it sleep for many more years.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: They dare not.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: Let us not pull the chestnuts out of the fire for them. Let them come separately before the House saying what action they have taken. It is really an escape that this amendment is giving to the Government. But I do not want to touch upon that aspect at all.

I would really like to know why the Government has not taken action up till now. The Minister of Parliamentary Affairs was quick enough to get this amendment round the House, but nobody on behalf of the Government has explained what is the Government's reaction to the Fiftieth Report of the Public Accounts Committee. No reaction at all.

As an ex-Member of the Public Accounts Committee I know that Action-taken reports are to be submitted to the Public Accounts Committee. Have they submitted an action-taken report on this? No doubt, in the matter of action-taken reports, they refer only to the recommendations made and the difficulties that they face. But in the Fiftieth Rerort a positive recommendation as regards what should be done in the case of Shri S. C. Mukherjee had been made. When a report points out certain things to Government, Government has to act upon it and report back to the Committee.

[Shri Dattatraya Kunte]

Then, in 1966, the Government gave one more assurance to these Committees that any recommendation of the Committee will be accepted by Government and, in case a recommendation is not to be accepted, the non-acceptance will be at the ministerial level or at the Cabinet level. Therefore, having accepted the Committee's report binding on the Government, why has the Government not acted during the 3-4 years? That is a moot point. One really does not understand why this has happend. Why are they, including the ex-Minister who has now become the leader of the opposition, a prospective Minister or the leader of the House, according to Mr. Madhu Limaye, in a hurry to pull the chestnuts out of fire?

Let us limit ourselves to its scope. We want to punish this Officer for the contempt of the House and for giving false evidence, and what that punishment should be. If the leader of the Opposition, the leader of the Swatantra Party and the leader of the Jan Sangh Party, want the officer to be punished, given the maximum punishment, let them indicate what that maximum punishment is. Otherwise, this working and the speeches they made would appear to be very strong but, in effect, they might lead us nowhere except the reprimand that he will get from this House. Therefore, I am not in a position to accept the amendment in spite of the appeal made for unanimity to agree to the amendment because that amendment might not serve the purpose which these able men have in their mind.

**श्री रणधीर सिंह** : चेयरमैन महोदय, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि अगर उनको रेप्रिमन्ड किया जाये तो इससे कोई हाउस की तौहीन होती है या इफेक्टिवलेस पेनाल्टी का काम होता है। हमारे देश की परम्परा है कि पंचायतें भी जहां होती हैं वहां भी आदमी पर एक पाई भी जुर्माना किया जाता है तो इससे उस आदमी को ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिलिएशन होता है। पीनल कोड में दफा 191 और 193 में सात साल की सजा है लेकिन जो बेशर्म और झूठ बोलने वाले लोग हैं उनपर अगर सात साल के बजाय 14 साल की सजा भी कर दी जाये तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी खानदानी आदमी को अगर रेप्रिमैन्ड भी कर दिया जाये तो वही उसके लिए मौत की सजा के बराबर है। इसलिए मैं आपकी मार्फत इस हाउस से कहना चाहता हूं कि इस मामले कोप्रेस्टीज का मामला न बनाया जाये बल्कि इससे इस हाउस की डिग्निटी, प्रेस्टीज और ग्रेस बढ़ेगी। एक आफिसर जिसने झूठ बोला था उसको अगर यह हाउस रेप्रिमैन्ड करता है तो यही उसके लिए कालापानी की सजा है।

मैं इस गवर्नमेन्ट का कोई लम्बा चौड़ा ठेका तो नहीं उठाता लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अगर यह हाउस और पार्लमेन्ट सुप्रीम है और गवर्नमेन्ट छोटी है क्योंकि यह हाउस पचास करोड़ आदमियों का है और गवर्नमेन्ट में थोड़े लोग हैं तोफिर अगर यह हाउस रेप्रिमैन्ड करेगा तो गवर्नमेन्ट न सिर्फ उसका सीरियस व्यू लेगी बल्कि उसका एक वाईडिंग इफेक्ट भी होगा और फिर वह आदमी रहेगा कैसे जिसको कि पार्लमेन्ट ने कह दिया हो कि यह फिट नहीं है सर्विस में रहने के लिए? फिर वह आदमी गवर्नमेन्ट सर्विस में रहेगा कैसे? इसलिए मैं खासतौर पर कहना चाहता हूं कि जहांतक मेरिट्स की बात है, श्री मधु लिमये जी ने एक एक बात जो कही मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं और ये जो आफिसर्स हैं नीचे से लेकर ऊपरतक और जो समझते हैं कि यह गवर्नमेन्ट और पार्लमेन्ट सब तुम्हारे नीचे है और तुम्हीं सारे देश की अक्ल रखते हो और सभी को उल्लू बना सकते हो उनको पता चलेगा कि ज्यादा अक्लमन्द आदमी का इलाज क्या होता है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि श्री मधु लिमये जी ने जो बात कही है, पिछले दस साल से उनकी कोशिश रही है उसकी मैं ताईद करता हूं कि इससे इस हाउस का और मेम्बरान पार्लमेन्ट का बेकार बढ़ा है।

सारे देश में जो एक ब्यूरोक्रैसी बैठी हुई है जोकि अपने को स्टील फ्रेम समझती है उनका दिमाग इससे सही हो जायेगा और वह समझ जायेंगे कि वह कहां हैं। इसका एक अच्छा असर पड़ेगा लेकिन मैं समझता हूं कि सजा देने का अच्छा असर नहीं होगा। यह जो कहा गया कि बच्चों को तीन दिन की सजा दी गई वहां पर इस रूल का एप्लीकेशन नहीं होता है, वह बात दूसरी थी। यहां तो इतना करने से ही एक आई सी एस की सारी सर्विस खत्म हो जायेगी और सारे देश में एक तहलका सा मच जायेगा। एक आई सी एस की लेवेल का आदमी पार्लियामेंट के सामने आये और इस तरह की बात वहां कहे तो क्या पार्लियामेंट की इज्जत रह जायेगी? मैं आपकी मार्फत हाउस से कहना चाहूंगा कि जो अमेंडमेंट डा० राम सुभग सिंह, श्री बाजपेई और दूसरे साथियों ने दिया है, जिसमें मेरा नाम भी भी जुड़ा हुआ है, सिवा उसके मानने के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वही सही रास्ता है। उन्होंने कहा कि हमने बीच का रास्ता ले लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि वही असली रास्ता है, अक्लमन्दी का रास्ता है, ग्रेस का रास्ता है। इससे हमारी और पार्लियामेंट की इज्जत बढ़ेगी। लोग समझेंगे कि इस सावरेन पार्लियामेंट के सामने एक अफसर ने हिम्मत की झूठ बोलने की उन लोगों के सामने जो देश के बड़े से बड़े नेता हैं, बावजूद इसके कि वह भगवान का नाम लेकर आता है, बावजूद इसके कि खुदा को हाजिर नाजिर समझ कर कहता है कि सही बात कहूंगा, वह झूठ बोलता है, यह झूठा आदमी है।

**16 hrs.**

फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर यह कहा गया है कि "एग्जाम्पलरी" पनिशमेंट दिया जाये, वहां "मैक्सिमम पनिशमेंट" जोड़ दिया गया है। मैक्सिमम पनिशमेंट से तो फुल डोज हो जाती है। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट तो थोड़ा भी हो सकता है। तीन चार दिन का इम्प्रेजनमेंट भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट से तो उसका भट्टा ही बैठ जायेगा। अगर हम यहां पर मैक्सिमम कह दें तो उससे आगे और क्या हो सकता है? साथ ही साथ हमने यह भी दे दिया है कि टाइम बाउंड ऐक्शन होगा। न सिर्फ यही, बल्कि उसकी रिपोर्ट भी की जायगी पार्लियामेंट को। इस तरह से तो ऐडमिनिस्ट्रेशन को भी नोटिस है कि न सिर्फ ऐक्शन वह ले, जैसा रेजोल्यूशन चाहता है बल्कि यूनेनिमस रेजोल्यूशन होगा कि उसको सजा दी जायेगी। उसको मोस्ट अनइक्वीवोकल टर्म्स में कंडेम किया जायेगा और गवर्नमेंट से कहा जायेगा कि तुम ऐक्शन लो। अगर तुमने ऐक्शन नहीं लिया तो तुम्हारा कान पकड़ कर खींचा जायेगा बतलाओ क्या ऐक्शन लिया, और उस ऐक्शन पर हम डिबेट कर सकेंगे।

लोक सभा की हिस्ट्री में यह एक यूनीक ऐक्शन होगा। इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी मजबूती और ईमानदारी आयेगी। वह लोग डरेंगे भी कि पार्लियामेंट हमको देख रही है और कहीं ऐसा न हो जाये कि कोई आ कर झूठ बोल जाये। वह ठीक होंगे ही साथ ही औरों के लिये यह डंडा होगा कि अगर कोई चीज ठीक नहीं होगी तो हमेशा उसकी नोटिस ली जा सकती है।

मैं ज्यादा वक्त न लेकर आपका मश्कूर हूं कि आपने मुझको मौका दिया क्योंकि अमेंडमेंट मेरे नाम में भी है। मैं सारे हाउस से चाहूंगा कि वह इसको मंजूर करे। जैसा श्री मिश्र ने कहा सबका व्यू यह है कि इसको मान लिया जाये। इसमें कोई डिसेशन नहीं होना चाहिये। सब लोग इसको यूनेनिमसली मान लें। अगर ऐसा हुआ तो हमारी इज्जत होगी साथ ही जो हमारी गवर्नमेंट का परपज है, जो इंटेंट है वह भी फुलफिल होगा।

SHRI TENNETI VISWANATHAM: Mr. Chairman, Sir, the question here is a very

[Shri Tenneti Viswanatham]

limited one. The Privileges Committee have already given us a unanimous recommendation. The recommendation by itself is a very good recommendation, in my opinion. There is not much difference in conveying the censure to the man in writing and calling him here and reprimanding him. But, if that pleases the Government, they may do so. So far as I am concerned, if my voice should prevail, I will be content with conveying the displeasure of this House to the officer concerned.

Mr. Kunte has raised the other point, namely, whether we can make a recommandation to the Government to punish the officer. Certainly we can. Really, the recommendation consists of two parts and the second part is requesting the Government to take action against him because the contempt itself has arisen out of an attempt by the officer to mislead the Public Accounts Committee with regard to certain transactions to which he was a party. That itself proves, if this is probed into, their might be several other kinds of irregularities in which not only he, but other also might be involved.

The Government is now fully incharge of the entire matter. The trouble with this Government, as far as I know, is this. Whenever the PAC makes a recommendation, the Government do not follow it up, especially when the recommendation is against some highly placed officers. That is the history of this Government. During the last 20 years or 25 years we have found that strong recommendations have been made against highly-placed officers; but Government never took action. The result is what we are seeing today. I hope at least now the Government will make up its mind to follow up the recommendations and take action on the basis of the recommendations, serve notice upon the officer and award suitable punishment. There should be no difficulty in that. This officer had the courage to go and misrepresent facts before the Committee. That itself is an act of misdemeanour. He can be removed from service. Article 311 will not come in the way at all. Naturally, an officer who has indulged in doubtful transactions, who has mislead the Public Accounts Committee, can no longer be trusted in Government service. The case of this particular gentleman has come before us because the Government was sleeping all along. But, probably, if there is a Madhu Limaye for every other misdemeanour pointed out by the P.A.C. perhaps more officers would have come up for discussion before the House.

As others have congratulated Mr. Madhu Limaye, I certainly congratulate him on the persistence with which he has brought up this matter now before us for discussion although up this is 10 years old. It also speaks volumes against this Government. For 10 years they have been sleeping in regard to such officers belonging to a department, about which there has been so much public agitation and public indignations, in which huge rackets were going on.

Now at least if they want to open up a new chapter in the behaviour of our public servants, they must follow up the recommendations of the Committee, particularly in the light of the strong speeches made by other hon. Members, If the Government makes up its mind to follow up the recommendations, even before the matter comes up before the Privileges Committee or the P.A.C., the officers will behave well. When officers behave well, there will be clean administration. If there is clean administration, there will not be wastage. If there is no wastage, there will not be much of taxation. The country can make all-round progress.

The Public Accounts Committee is an important committee of Parliament. This report came out in October. The Government had not told the House what action they took on these recommendations; they were sleeping all along even after October, when they should have initiated action. So, I would like to know what action they have proposed to take or they have already taken against the officer.

There are two aspects involved here. One is contempt of the House. He is punished when we convey the censure of this House to the officer concerned.

On the second aspect, the Government should immediately follow up the recommendation and give notice to the officer and take appropriate action. A highly placed officer who has got the courage to come up before

the P.A.C., trying to cover up his faults by misleading it, can no longer be trusted in Government service.

SHRI N. K. P. SALVE : I rise to support the amendment moved by Dr. Ram Subhag Singh, which, as I was told by Shri Atal Bihari Vajpayee, was in fact drafted by Shri Nath Pai, and, I suppose, signed by Shri Atal Bihari Vajpayee and some others. I wholeheartedly support that amendment.

Anyone who commits contempt of the House or of an important committee of the House like the Public Accounts Committee must come in for the strictest censure.

I also wholeheartedly associate myself with all those Members who have congratulated Shri Madhu Limaye so warmly. It is in fact a tribute to his scholarship, his vigilance and his erudition. In fact, when I was in the committee myself, I realised what scant respect was shown by the bureaucrats to these committees. Several times, one thought when the secretaries appeared, they assumed an air of arrogance which might have been justified because they have not known any other attitude, but the ignorance was absolutely unjustified. They never read the papers ; they never read the briefs properly, but they came there and looked for instructions from behind, like some of the lawyers of whom you must be aware, Sir, who turn to their client or their accountant or clerk or somebody else for instructions about how to reply to a point. I think this is one such case, which has very rightly been caught by Shri Madhu Limaye.

But what I consider of utmost importance, so far as the Honse is concerned, is something which has invoked the fury of the House and the wrath of the House, namely that this evidence related to some transactions which happened to be saturated with the utmost of venality and corruption possible. If the evidence related to a matter which did not amount to something more than a stinking record in foreign exchange, then, maybe, the House could have been a little more charitable, and maybe, Shri Madhu Limaye could have been a little colder.

As you know, these transactions related to pre-import of certain steel, certain stainless steel in the hope of future exports, which exports never materialised. I find that hon. Minister is not here at the moment, but I understand that even today, despite all this racket, they are still allowing indiscriminate imports of steel, but I hope that these kinds of things would not recur.

At any rate, I must submit that it is necessary for us here at this juncture to determine what exactly is the lapse of these two officers..

SHRI R. D. BHANDARE : One only.

SHRI N. K. P. SALVE :....or what the lapse of the officer, Shri Mukherjee is. I do not for a moment want to defend Shri Mukherjee. In my opinion, he is guilty of a technical lapse, and since he is guilty of a technical lapse, he must come in for punishment. But for the sake of proper record, although I do not for a moment want to defend him, it is necessary for us....

AN HON. MEMBER : Technical lapse ?

SHRI N. K. P. SALVE : I shall show presently from the report of the Privileges Committee itself that it is technical. Let it not be said that because someone is not here, we are attacking him. I do not know him for Adam, I do not know this gentleman, but I am only going by the report of the Privileges Committee, and from the proceedings, to me, it appears, that there were two charges on this gentleman. The first charge was that he made certain statements regarding pre-imports and exports. For that, he has been completely exonerated. In fact, that charge impinged upon the basic question of the corruption involved in these transactions. But he has been completely exonerated of that.

But the second charge was a charge relating to the change of bank guarantee. What is of utmost importance in this is this, that the basic change brought about in the bank guarantee has been accepted as something defensible and as something desirable. That is what the finding of the committee is. While giving evidence before the committee, Mr. Mukherjee made a statement that the changes in the bank guarantee were made at the instance of the

[Shri N. K. P. Salve]
Government Solicitor and not by him. To that extent, he is guilty of the contempt of the House. I have no doubt about it in my mind. For that, he should be punished, but no more, because the changes as such have been approved by the Privilges Committee. I would invite your attention to a few lines at page 41 of the committee's report.

SHRI SRINIBAS MISRA: No, no; it is in the Steel Transactions Inquiry Committee's report.

SHRI N. K. P. SALVE: That is what is written here, at any rate, namely:

"In fact, Shri P. C. Padhi in his minute of dissent to the report of the Committee of Inquiry...."

SHRI MADHU LIMAYE: It is only a quotation from the report of the Steel Transaction Inquiry Committee's. It is not the finding of the committee. The ending is that they have held him responsible for contempt.

SHRI N. K. P. SALVE: This is the finding of the committee which inquired into the matter, and I want to bring it on record. This is the finding of the committee when inquired into that. It reads thus:

"In fact, Shri P. C. Padhi in his minute of dissent to the report of the Committee of Inquiry has found Shri Mukherjee responsible for having misled Shri Wanchoo while he was giving evidence before the PAC to believe that no alterations had been made in the Solicitor's draft."

"On the other hand, the majority of the Committee of Inquiry have pointed out that by changing it" (that is, the bank guarantee in the way in which Shri Mukherjee had done) "the bank guarantee was made workable and easily enforceable."

I have not had a look at the bank guarantee.

SHRI MADHU LIMAYE: It was not the observation of the Paiviliges Committee or the PAC Sub-Committee.

SHRI N.K.P. SALVE: I stand corrected. It is the observation of the Sarkar Committee went into the question of the steel transactions. So far as the finding of the Privileges Committee is concerned, it is in these terms:

"The Committee agrees with the finding of the Public Acconnts Committee that a material change in the form of the bank guarantee was made by Shri Mukherjee and not by the government Solicitor".

That means, the change was made by Shri Mukherjee and not by the solicitor. I quote further:

"Therefore, a misrepresentation of the position to this extent was made by Shri Mukherjee".

*To this extent.* Therefore, Shri Mukherjee is guilty of having misrepresented the position before the Committee to this extent, that whereas he made the change in the bank guarantee, he said it was the Government Solicitor who had brought about a change. To this extent, he is guilty; however small the lapse may be, it is very necessary that this incorrigible bureaucracy is taught some lesson or the other. Let them take us a little more seriously.

I wholeheartedly support the amendment of Dr. Ram Subhag Singh's.

SHRI R. D. BHANDARE: Since there are certain facts mentioned by Shri Madhu Limaye, I want to put the record straight. The Privileges Committee did not want to shirk its responsibility, but in its wisdom on 16-9-69, it referred the matter to the Public Accounts Committee...

SHRI MADHU LIMAYE: Before he became Chairman. Let him say that.

SHRI R. D. BHANDARE: That I think, goes without saying.

It was referred back long before I became Chairman. The Chairman of the PAC appointed a sub-committee to inquire into the whole matter and come to its conclusions. Then that report and conclusions were referred back to

the Privileges Committee. Going through the report, we found that when the inquiry was made by the PAC Sub-Committee, Shri Wanchoo was not the Secretary when the transaction took place. It took place in 1960, when Shri S. C. Mukherjee was the Deputy Iron and Steel Controller. Shri Wanchoo was then not in that Ministry. When the inquiry was made in 1966, Shri Wanchoo had given evidence on behalf of the Ministry. At the time of tendering the evidence, he did it according to the files. At that time, Shri Mukherjee did not correct Shri Wanchoo. To that extent, Shri Mukherjee connived at it in keeping quiet and allowing Shri Wanchoo to make an incorrect statement.

SHRI MADHU LIMAYE : Let him please read from p. 43.

SHRI R. D. BHANDARE : The report is before members. They must have gone through every word of it.

SHRI MADHU LIMAYE : I hope so.

SHRI R. D. BHANDARE : Therefore, I need not quote it.

Coming to the amendment itself, since legal luminaries like Shri Nath Pai, Shri Randhir Singh and others are behind it, I did not want to say anything. But I do not know what meaning should be attached to the term 'maximum punishment'. If we go through the Law of Lexicon by Maxwell, I do not think this term will carry any meaning, because we have the Constitution and rules for civil conduct. Both have to be followed. Art. 311(2) shall have to be followed at the time of meting out the punishment. When I had moved my amendment for the acceptance of the original report with some consequential action, it was thought it would suffice. But now wiser and more learned friends wanted to put in this amendment. I am simply mentioning that the term 'maximum punishment' does not signify anything in the light of what I have said.

SHRI N. K. P. SALVE : That was the minimum they could agree to.

SHRI R. D. BHANDARE : Since we act on the theory of checks and balances, we have accepted this expression "maximum punishment", but this is the factual position.

With these words I put the record straight that the Privileges Committee did not shirk its responsibility, the matter was put before the PAC, the PAC appointed a Sub-Committee which went through the evidence. When the report was referred back to the Privileges Committee, as you know, there are two courses open, either to hear the evidence *de novo* or act on the record and the report as is submitted. Instead of going through the same process of taking evidence, we simply relied on the record because in our wisdom we thought that the record was sufficient to come to certain conclusions.

SHRI MADHU LIMAYE : You did not want to contradict the PAC.

SHRI R. D. BHANDARE : The contribution of the Privileges Committee was to go through the report *in toto*, evaluate the report and the evidence submitted and come to the conclusion.

**श्री शिवचन्द्र झा** : सभापति महोदय, श्री मधु लिमये का जो प्रस्ताव है, मोटे तौर पर हम सब उससे सहमत हैं। श्री एस० सी० मुकर्जी ने जो गुनाह किया है, उसके लिए उनको सजा देने की बात इस प्रस्ताव में कही गई है। उनके दो गुनाह सामने आते हैं। उनका एक गुनाह तो वे धांधलियां हैं, जो उनके आयरन एण्ड स्टील कंट्रोल रहते हुए इस्पात के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में हुई, जिनसे देश को नुकसान हुआ। उनका दूसरा गुनाह यह है कि उन्होंने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने आकर गलत गवाही दी और फैक्ट्स को डिसटार्ट किया। उनके दो गुनाह हमारे सामने आते हैं : एक तो अफसर के रूप में गलत काम करना और दूसरा पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने गलत गवाही देना। इसके लिए उनको सजा देने की बात हमने सोचनी है।

डा० राम सुभग सिंह, श्री नाथ पाई और श्री बाजपेयी आदि ने जो संशोधन रखा है, जिसका समर्थन श्री रणधीर सिंह ने किया है, वह बहुत कान्ट्राडिक्टरी है। अगर वे यहीं तक

[श्री शिवचन्द्र झा]

रुक जाते कि "सम्मन्ड बिफोर दि बार आफ दि हाउस एंड बि रेप्रिमेंडिड" तब तो उनकी बात समझ में आ सकती थी लेकिन उसके आगे उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि सरकार कानून के मुताबिक उनको सजा दे और फिर उसके बारे में हाउस को रिपोर्ट करे। श्री बाजपेई ने इस विषय में कहा कि हम फिर इस प्रश्न पर विचार करेंगे और यह मामला फिर उठाया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस संशोधन से इस पर एक रिफ्लेक्शन आता है। अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि श्री मुकर्जी ने गुनाह किया है, तो वे यह फैसला करें कि हम उसको अमुक सजा देंगे। श्री मधु लिमये का प्रस्ताव क्लीयर-कट है कि हम उसको सात दिन की कैद की सजा दें। उसमें कोई दुविधा या शंका नहीं है। अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि वह सजा कम है और उसको ज्यादा सजा देनी चाहिए तो वह उसके लिए यहां संशोधन रखें। लेकिन वह देश के सामने यह इम्प्रेशन न जाने दें कि यह हाउस इन्साफ करने के लिए या सजा देने के लिए काम्पीटेंट नहीं है। उनके संशोधन से तो यह जाहिर होता है कि इस हाउस के पास न्याय करने का कोई मापदंड नहीं है। वे कहते हैं कि हम श्री मुकर्जी को रेप्रिमेंड करें और फिर उनको सजा देने के लिए मामले को सरकार के पास भेज दें और अगर सरकार कम या ज्यादा सजा देती है, तो हम फिर उस पर विचार करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि किस तरह न्याय किया जाना चाहिए और कितनी सजा देनी चाहिए, क्या उनके पास इसका कोई बैरोमीटर नहीं है। इससे लगता है कि उनकी स्प्लिट पर्सनेलिटी है और ड्युअल नीति है। उनका संशोधन एम्बिगुअस है। इस संशोधन से इस सदन की मर्यादा पर रिफ्लेक्शन होता है। मैं तो यह समझता हूं कि जिन सदस्यों ने यह संशोधन दिया है, उनके खिलाफ प्रिविलेज का मामला बन जाता है। श्री मुकर्जी को रेप्रिमेंड करने की बात तो सही है, लेकिन इस मामले को सरकार के पास भेजने की बात मेरी समझ में नहीं आती है इस-लिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

डा० राम सुभग सिंह ने कहा कि देश में अफसरशाही का राज है और इस तरह गलत काम करने वाले अफसरों को सख्त सजा देनी चाहिए। इस स्थिति में उनको कौन रोकता है कि वे ठंडे दिल से सोचें कि हम इस अफसर को यह सजा देंगे। सरकार के पास मामले को भेजने के लिए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उससे साबित हो जाता है कि भले ही वह इधर से उधर चले गये हों, लेकिन अफसरशाही के प्रति उनका मोह और ममता गई नहीं है। यह समझते हैं कि वह एक दिन फिर अफसरशाही के घोड़े पर चढ़ेंगे और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। अफसरशाही का यह प्रशासन भ्रष्ट है, राटन टु दि कोर है। इस संशोधन से यह मालूम होता है कि वह इस प्रशासन को साफ नहीं करना चाहते हैं। इससे उनकी आइडियालोजी का भी पता चल जाता है। उनका यह स्टैंड ठीक नहीं है।

मैंने यह संशोधन दिया है कि श्री मुकर्जी को एक हफ्ते की कैद की सजा देनी चाहिए और उसके साथ-साथ पांच हजार रुपये जुर्माना होना चाहिए। श्री मधु लिमये ने केवल सात दिन कैद की बात कही है। केवल कैद की सजा देकर उसका क्या होगा ? श्री रणधीर सिंह ने खानदानी आदमी की बात कही है ये लोग प्रिवीपर्स खत्म करते हैं और खानदान की बात करते हैं। जब रूलर्ज यह कहते हैं कि हमारी इज्जत और डिग्निटी खत्म हो रही है, तो फिर क्या उनका स्टैंड सही नहीं है ?

मैं समझता हूं कि एक हफ्ते की कैद से कुछ नहीं होगा। जब तक उसको मानिटरी सजा नहीं दी जायेगी, तब तक वह महसूस नहीं करेगा कि उसको पूरी सजा दी गई है।

जहां तक स्टील उद्योग का सम्बन्ध है, ये सब धांधलियां प्राईवेट सेक्टर में हो रही हैं, इसलिए प्राईवेट सैक्टर के स्टील उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

माननीय सदस्यों के संशोधन में दुविधा है। इसलिए उसको कतई नहीं माना जाना चाहिए। उससे तो यह जाहिर होता है कि हम न्याय करने के लिए इनकाम्पीटेंट हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारा क्लीयरकट स्टैंड होना चाहिए कि हाउस को इन्साफ करने और सजा देने का हक है। इसलिए श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को मान लिया जाये और अगर उसमें कोई संशोधन करना है, तो फिर मेरा संशोधन माना जाये।

SHRI RAGHU RAMAIAH: Government certainly understand the gravity of the situation. That is why when this matter was first brought up, one of our own Members Shri Randhir Singh himself associated with the amendment suggested by six of them.

As regards the amendment of Shri Kalita that it be reported in seven days, it has been rightly pointed out by Shri Vajpayee and in a way by Dr. Ram Subhag Singh and others that there are certain constitutional procedures; Mr. Kunte also referred to it; these procedures have to be followed in cases of this type. There is Article 311 and then there are also certain rules framed under the Constitution. In certain cases consultation with the UPSC will be necessary.

I understand that it is the intention of the sponsors of this amendment and of this House that every right shall be given to the person charged to defend himself in accordance with the Constitution; it is in that spirit that we are passing this Resolution. I want to make this doubly clear, as I understand it is the intention of the House not to deprive any person of any constitutional right provided under the Constitution. We are in entire agreement with the amendment sponsored by six persons including Shri Randhir Singh and we associate ourselves with it.

**श्री मधु लिमये** : अध्यक्ष महोदय, अब मेरे लिये दिक्कत यह है कि जिन नेताओं ने यह संशोधन रखा है वह इस वक्त सभा में मौजूद नहीं हैं।

**श्री शिवनारायण** : मैं बैठा हूं।

**श्री मधु लिमये** : राम सुभग सिंह जी और जिन नेताओं ने संशोधन रखा है उनकी बात मैंने कही। मेरे लिए आप भी उतने ही पूजनीय हैं जितने दूसरे हैं लेकिन जिन्होंने संशोधन रखा है उनके लिए मैंने कहा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो तीन आरोप इन अफसरों के खिलाफ थे उनमें से दो आरोपों के बारे में उन्होंने यह कहा है कि वह दोषी हैं। लेकिन उन्होंने सदन के अपमान का जो गंभीर अपराध है वह नहीं किया है, जैसे वांचू साहब के बारे में कहा है।

सफा 42 पर उसमें कहा है :

> "The Committee agree with the findings of the Public Accounts Committee that although there was an omission on the part of Shri Wanchoo to bring to the notice of the Public Accounts Committee during his evidence before the Committee on the 10th March, 1966 certain instructions issued by the Ministry of Steel..." ete.

उन्होंने यह बात रखने में गलती की यह तो कमेटी मानती है लेकिन यह जानबूझ कर उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनको सन्देह का लाभ देते हैं।

दूसरे आरोप जो एस० सी० मुकर्जी के बारे में हैं उसके बारे में कमेटी कहती है :

> "The Committee also agree with the Public Accounts Committee that as Shri S.C. Mukherjee had not himself given evidence on this point before the Public Accounts Committee, Shri S. C. Mukherjee cannot be

[श्री मधु लिमये]

> held directly responsible for the Public Accounts Committee having been misled on this point, although he could have, if he had been alert, corrected Shri Wanchoo when he was giving evidence before the Public Accounts Committee."

उनके सामने वह गलत जानकारी दे रहे थे और यह गलत जानकारी है यह मुकर्जी को मालूम था तो मुकर्जी उस समय इस गलती को सुधार सकते थे, यह कमेटी स्वयं मानती है। तो इनके जो अपराध हैं वह केवल सदन के अपमान के अपराध नहीं हैं। दूसरे सारे अपराध भी हैं। अब आप इस संशोधन के बारे में कह रहे हैं कि हम उनको यहां बुलाकर चेतावनी देंगे और उसके बाद सरकार उनको अधिक से अधिक सजा दे। किन कारणों को लेकर सजा दे? सदन का अपमान किया उसके लिये सजा दे या दूसरे जो अपराध किये हैं जो सदन के अपमान के बराबर नहीं हैं उनके लिये भी दे? तो अब यह नेता लोग आ रहे हैं। मेरी प्रार्थना अगर यह सुनेंगे तो मैं भी इनकी कुछ बातों की कदर करूं यह मैं चाहता हूं। कोमलता के बारे में जो मैंने कहा उसके ऊपर इतना विवाद नहीं होना चाहिए था क्योंकि भवभूति ने उत्तर रामचरित में कहा है:

वज्रादपि कठोराणि मृदूनिचकुसुमादपि। तो इन भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ तो वज्र से भी कठोर होना है लेकिन आप लोगों के सामने तो हमें मृदु होना ही पड़ेगा। तो हम एक ही परिवर्तन उसमें चाहते हैं। वह फायदे का है उसमें ऐंड हिज अदर लैप्सेज जोड़ दिया जाय। वरना अपमान के लिए आप दंड उनको दे रहे हैं। तो ड्युअल पनिशमेंट का भी सवाल कोर्ट में उठ सकता है। संविधान की दफा 20 के तहत यह कहा गया है कि एक ही जुर्म के बारे में दो दफा सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए "ऐंड हिज अदर लैप्सेज" आप जोड़ेंगे तो जैसे ऐडमिनिस्ट्रेटिव ला की बात आपने की उनके द्वारा दूसरे जो दुर्व्यवहार या दुराचरण हुए हैं उसके बारे में उनको सजा हो सकती है। इसलिए अटल जी, राम सुभग सिंह जी और रघुरमैया जी से मेरी एक प्रार्थना है कि मेरा इतना छोटा सा संशोधन मान लीजिये तो आप चाहते हैं कि एक राय से यह मामला तय हो तो मैं भी उसके ऊपर डिवीजन वगैरह नहीं कराऊंगा। ·· (**व्यवधान**) ·· ऐंड हिज अदर लैप्सेज यह शब्द जोड़ दिए जायं तो कोई झंझट नहीं होगा।

SHRI RAGHU RAMAIAH: I sm sorry I am not in a position to accept the amendment moved.

**श्री मधु लिमये**: आपको क्या आपत्ति है?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: क्या लैप्सेज हैं?

**श्री मधु लिमये**: अभी तो मैंने पढ़कर सुनाया कमेटी की रिपोर्ट से। बैंक गारंटी फार्म में परिवर्तन किया यह कोई लैप्स नहीं है?

**श्री ब० रा० भगत**: यह तो प्रिविलेज में आता है।

**श्री मधु लिमये**: प्रिविलेज में कैसे आता है? यह तो झूठ गवाही में आता है। या बिलकुल साफ आरोप है, बैंक गारंटी में परिवर्तन करना बिना किसी से पूछे जिससे सरकार का घाटा हो ·· (**व्यवधान**) ·· नहीं तो फिर तो डिवीजन होगा।

SHRI B. R. BHAGAT: Regarding the findings of the Sarkar Committee on Shri Mukherjee, action has been taken. The findings were sent to the Central Vigilance Commissioner who recommended that Government's displeasure be conveyed to him. We have done that.

**श्री मधु लिमये**: यही होने वाला था। तो आप फिर मुझे तीन मिनट कह लेने

दीजिए। अब मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूं। और मैं इस पर डिवीजन कराऊंगा और चेतावनी देकर यह कहूंगा कि आप मेरे विरोध के बावजूद इसको पास करने जा रहे हैं लेकिन मैं चेतावनी देता हूं कि इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी और मेरे यह शब्द हैं जो रिकर्ड पर आएंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे यह हम लोग देखेंगे· · (व्यवधान) · ·

SHRI NATH PAI: Regarding the last apprehension expressed by Mr. Limaye, we can point out that this is a resolution of the House. The recommendation of the House is mandatory. If the Government does not implement it, Government stands condemned. The recommendation is mandatory; only polite lauguage has been imported by us saying "it recommends maximum punishment." If the Government fails to carry out the mandate, Government stands condemned and a motion of privilege will be brought against the Minister of Parliamentary Affairs and other Ministers. I do not think the Government dare defy the recommendation of the House.

MR. CHAIRMAN: Now I will put the amendment.

SHRI DATTATRAYA KUNTE: What about my point of order?

MR. CHAIRMAN: I have already disposed of it. There is no force in your point of order.

**श्री मधु लिमये**: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन पर संशोधन दिया है उस पर आप वोट ले लीजिये।

**सभापति महोदय**: वह मेरे सामने नहीं है।

**श्री मधु लिमये**: वह बाद में अभी मैंने दिया है। आप आखिर तक लेते रहे हैं। अगर टेकनिकलिटी में जाइएगा तो इनका भी नहीं ले सकते। आप मेरे संशोधन को भी लीजिए। मैंने लिखकर दिया है। मैं इतना जोड़ना चाहता हूं· · · ·

MR. CHAIRMAN: All right; you may move your amendment.

SHRI MADHU LIMAYE: I beg to move:

'That in amendment No. 3 moved by Dr. Ram Subhag Singh, *after* "gravity of the offence", *insert*—"and his other lapses".'

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That in amendment No. 3 moved by Dr. Ram Subhag Singh, *after* 'gravity of the offence' *insert* 'and his other lapses'."

*The Lok Sabha divided*

**AYES**

*Division No. 12*] [*16.46 hrs.*

Abraham, Shri K. M.
Amjad Ali, Shri Sardar
Atam Das, Shri
Banerjee, Shri S. M.
Basu, Dr. Maitreyee
Bhagaban Das, Shri
Desai, Shri Dinkar
Jha, Shri Bhogendra
Jha, Shri Shiva Chandra
Kalita, Shri Dhireswar
Kunte, Shri Dattatraya
Limaye, Shri Madhu
Misra, Shri Srinibas
Mohammad Ismail, Shri
Molahu Prasad, Shri
Nath Pai, Shri
Nihal Singh, Shri
Patel, Shri J. H.
Patil Shri N. R.
Ram Charan, Shri
Ray, Shri Rabi
Samanta, Shri S. C.
Satya Narain Singh, Shri
Shastri, Shri Ramavatar
Shastri, Shri Sheopujan
Thakur, Shri Gunanand
Umanath, Shri
Viswambharan, Shri P.
Yadav, Shri Jageshwar

**NOES**

Ahirwar, Shri Nathu Ram
Agadi, Shri S. A.
Ahmed, Shri F. A.
Amin, Shri R. K.
Anjanappa, Shri B.
Bajaj, Shri Kamalnayan
Barua, Shri Bedabrata

Basumatari, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhandare, Shri R. D.
Chandrakar, Shri Chandoolal
Chavan, Shri Y. B.
Damani, Shri S. R.
Dandeker, Shri N.
Deshmukh, Shri B. D.
Devgun, Shri Hardayal
Dixit, Shri G. C.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Gandhi, Shrimati Indira
Gautam, Shri C. D.
Gavit, Shri Tukaram
Ghosh, Shri Bimalkanti
Gowder, Shri Nanja
Heerji Bhai, Shri
Hem Raj, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V. N.
Jagjiwan Ram, Shri
Jamna Lal, Shri
Joshi, Shri Jagannath Rao
Kamble, Shri
Karan Singh, Dr.
Kesri, Shri Sitaram
Kisku, Shri A. K.
Kotoki, Shri Liladhar
Kureel, Shri B. N.
Lalit Sen, Shri
Madhok; Shri Bal Raj
Maharaj Singh, Shri
Majhi, Shri Mahendra
Marandi, Shri
Master, Shri Bhola Nath
Meena, Shri Meetha Lal
Mehta, Shri P. M.
Melkote, Dr.
Mishra, Shri G. S.
Mody, Shri Piloo
Muhammad Ismail, Shri M.
Mukerjee, Shrimati Sharda
Mulla, Shri A. N.
Nayar, Shrimati Shakuntla
Nayar, Dr. Sushila
Oraon, Shri Kartik
Pahadia, Shri Jagannath
Pant, Shri K. C.
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri S. B.
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Raghu Ramaiah, Shri
Rajasekharan, Shri
Ram, Shri T.
Ram Sewak, Chaudhary
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Rampur, Shri Mahadevappa
Ramshekhar Prasad Singh, Shri
Rana, Shri M. B.
Randhir Singh, Shri
Rao, Dr. V. K. R. V.
Reddy, Shri P. Antony
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Salve, Shri N. K. P.
Sambasivam, Shri
Sankata Prasad, Dr.
Sapre, Shrimati Tara
Savitri Shyam, Shrimati
Sayeed, Shri P. M.
Sen, Shri P. G.
Shah, Shrimati Jayaben
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri B.
Shastri, Shri Ramanand
Sheo Narain, Shri
Shinde, Shri Annasahib
Shiv Chandika Prasad, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Swaran Singh, Shri
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri K. N.
Tyagi, Shri Om Prakash
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Verma, Shri Balgovind
Virbhadra Singh, Shri
*Viswanatham, Shri Tenneti

MR. CHAIRMAN: The result** of the division is:

Ayes: 29; Noes 98;

*The motion was negatived*

---

*Wrongly voted for Noes.

**The following members also recorded their votes:

Ayes: Sarvashri Tenneti Viswanatham, A. Sreedharan, S. M. Joshi and S. A. Dange;

Noes: Sarvashri Bibhuti Mishra, Ram Dhan and R. V. Naik.

MR. CHAIRMAN : Now I am putting amendment No. 3 by Dr. Ram Subhag Singh and five others, to the vote of the House. The question is :

'That in the motion,—

*for* "committed to jail custody for a week"

*substitute* "summoned before the bar of the House and be reprimanded and the House do further recommend that the Government in the light of gravity of the offence administer to Shri S. C. Mukherjee maximum punishment under the law and report the same to this House."' (3)

*The motion was adopted*

MR. CHAIRMAN : Now, there are two other amendments, one of them standing in the name of Shri Shiva Chandra Jha. I am putting it to the vote of the House.

The question is :

'That at the end, *after* "week"

*insert*—"and be fined Rs. 5,000."'

Those in favour may please say "Aye".

SOME HON. MEMBERS : "Aye".

MR. CHAIRMAN : Those against may please say "No."

SOMS HON. MEMBERS : No.

MR. CHAIRMAN : I think, the "Noes" have it.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : The "Ayes" have it.

MR. CHAIRMAN : Let the lobbies be cleared....Order, order. The lobbies have been cleared.

SHRI RAGHU RAMAIAH : As the motion now stands there is no word as "week". How can there be an amendment to it then ?

SHRI NATH PAI : This amendment cannot be put to vote. After the amendment standing in the name of Dr. Ram Subhag Singh, Shri Atal Bihari Vajpayee and others is adopted, this amendment cannot be connected with the motion. We are making ourselves a laughing stock ; the records will make us a but of laughter for everybody.

MR. CHAIRMAN : Quite right. Now Shri Shiva Chandra Jha will realise the development that has taken place. The amendment moved by Dr. Ram Subhag Singh has been adopted by the House, with the result that some words which were there in the original Motion are no more there. His amendment says :—

'That at the end, *after* "week".'

That word is no more there ; therefore, this amendment is declared out of order.

Mr. Kalita, the same is the position with regard to your amendment. That is also declared out of order. Now, I put the Motion, as amended, to the vote of the House. The question is :

"That this House having considered the Twelfth Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 24th November, 1970, in which Shri S. C. Mukherjee, the then Deputy Iron and Steel Controller, has been held to have deliberately misrepresented facts and given false evidence before the Committee on Public Accounts and committed contempt of this House, do resolve that he be summoned before the bar of the House and be reprimanded and the House do further recommend that the Government in the light of gravity of the offence administer to Shri S. C. Mukherjee maximum punishment under the law and report the same to this House."

*The motion was adopted.*

---

**16.52 hrs.**

## DISCUSSION *RE* : ESTABLISHMENT OF COTTON CORPORATION OF INDIA —*Contd.*

MR. CHAIRMAN : The House will now take up further discussion on the statement laid